



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 24092021-229915
CG-DL-E-24092021-229915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
No. 280] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

(मामला सं. एडी-(ओआई)-28/2020)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन(एचएफसी) घटक आर-32 के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/33/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) को मै. एसआरएफ लिमिटेड (जिन्हें आगे ‘आवेदक’ या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) से एक आवेदन (जिसे “याचिका” भी कहा गया है) प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32” (जिसे आगे विचाराधीन उत्पाद या “पीयूसी” या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में अधिनियम और नियमावली के अंतर्ग पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/33/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 सितंबर, 2020 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई थी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- क. प्राधिकारी ने संबंधित नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 सितंबर, 2020 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई।
 - ग. प्राधिकारी ने दिनांक 28 सितंबर, 2020 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता एसोसिएशनों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रदान करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी।
 - घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और दूतावास को भेजी थी।
 - ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।
 - च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने पर प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को कई बार 20 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया था।
 - छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
 - i. मै. झेजियांग यंधि रेफ्रिजरेटर्स कं. लि.
 - ii. मै. दि चेर्म्स 3एफ फ्लोरोकेमिकल्स (चांगशु) कं. लि.
 - iii. मै. निन्कहुआ ग्रुप कं. लि.
 - iv. मै. सिनोचेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल (ताईकैंग) कं. लि.
 - v. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.
 - vi. मै. जिबो फेइयुआन केमिकल्स कं. लि.
 - vii. मै. सिसनोचेम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल कं. लि.
 - viii. मै. जिन्हुआ योंघी फ)लुओरोकेमिकल कं. लि.
 - ix. मै. हांगझोउ जुमिंग एम्प/एक्स कं. लि.
 - x. मै. डोंगयांग वेइहुआ रेफ्रिजरेटर्स कं. लि.

- xi. मै. झेजियांग क्यूझोऊ लियानझोउ रेफ्रिजरेट्स कं. लि.
 - xii. मै. लु सी केमिकल (हांग कांग) कं. लिमिटेड
 - xiii. मै. दि चेम्स केमिकल (शंघाई) कं. लि.
 - xiv. मै. डैकिन आरकेमा रेफ्रिजरेट्स एशिया लिमिटेड
 - xv. मै. झेजियांग लानतियान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्लुओरो मैटिरियल कं. लि.
 - xvi. मै. फ्लुओ शंघाई इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि.
 - xvii. मै. बीजिंग स्ट्रेगेट केमिकल्स कं. लि.
 - xviii. मै. जिबो फेइयुआन केमिकल कं. लि.
 - xix. मै. झेजियांग फोटेक इंटरनेशनल कं.
 - xx. मै. सिनोचेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि.
 - xxi. मै. झेजियांग ओरिएंट मल्टीटेक्स आई/ई कं. लि.
 - xxii. मै. एसीई प्रोसपर कारपोरेशन
 - xxiii. मै. डायानिक लिमिटेड
 - xxiv. मै. डैकिन फ्लुओरोकेमिकल्स (चीन) कं. लि.
 - xxv. मै. जियांगक्सी ली एंड मैन केमिकल लिमिटेड
 - xxvi. मै. एससी निंगबो इंटरनेशनल लि.
 - xxvii. मै. शानडोंग हुआन न्यू मैटिरियल कं. लि.
 - xxviii. मै. लियान्चेंग रुइजिन (हांग कांग) कं. लिमिटेड
 - xxix. मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओरो-केमिस्ट्री कं. लि.
- ज. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों और उनके संबंधित निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर और/या विधिक अनुरोध प्रस्तुत/दायर किए:-
- i. मै. झेजिंगा क्यूझोऊ जक्सिन फ्लुओराइन केमिकल कं. लि.(उत्पादक)
 - ii. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. (निर्यातक)
 - iii. मै. जिबो फेइयुआन केमिकल कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक)
 - iv. मै. शानडोंग डोंगहुई केमिकल कं. लि.(उत्पादक और निर्यातक)
 - v. मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर-केमिस्ट्री कं. लि.(निर्यातक)
 - vi. मै. फुजियान किंगलिअु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं. लि. (उत्पादक)
 - vii. मै. जियांगसु एनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. (उत्पादक)
 - viii. मै. ताइजिंग मेइलान न्यू मैटिरियल्स कं. लि. (उत्पादक)
 - ix. मै. ताइझोऊ क्यूइंगसोंग रेफ्रिजरेट न्यू मैटिरियल कं. लि. (उत्पादक और निर्यातक)
 - x. मै. सिनोचेम लानताइन फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि. (निर्यातक)
 - xi. मै. ताइकिंग मेइलान झिंगलान न्यू मैटिरियल्स कं. लि.(व्यापारी)
- झ. प्राधिकारी ने निमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थी:-

- i. मै. गोराखराम हरिबक्श
 - ii. मै. किर्बी रेफ्रिजरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - iii. मै. स्टालियन इंटरप्राइजिज
 - iv. मै. मंगली पैट्रोकेम लि.
 - v. मै. अजय एअर प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि.
 - vi. मै. गुजरात फ्लुओरो केमिकल्स लि.
 - vii. मै. स्टालियन इंडिया फ्लुओरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - viii. मै. कूलमेट रेफ्रिजरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. मै. चिलेयर साल्युशंस
 - x. मै. महिमा इंडिया प्रा. लि.
 - xi. मै. वैल्यु रेफ्रिजरेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - xii. मै. एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xiii. मै. नवीन फ्लुओरो इंटरनेशनल लिमिटेड
 - xiv. मै. विजय पैट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
 - xv. मै. श्रवण इंजीनियरिंग इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड
 - xvi. मै. सिकेलान केमिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xvii. मै. रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - xviii. मै. मेक्सफ्लुओरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. मै. टी.टी. इंटरनेशनल कं. लि.
 - xx. मै. वेईट्रोन इंटरनेशनल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट (कुनशान) कं. लि.
 - xxi. मै. एवन 9 स्टार फ्यूचर प्राइवेट लिमि.
 - xxii. मै. यूनिक जनरल ट्रेडर
 - xxiii. मै. कार्तिक ट्रेडर्स
 - xxiv. मै. हिंदुस्तान रेफ्रिजरेशन स्टोर्स
 - xxv. मै. कूल केम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
 - xxvi. मै. कूलेन रेफ्रिजरेट्स
- ज. इसके उत्तर में निम्नलिखित आयातकों या प्रयोक्ताओं ने जवाब दिया और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर/विधिक अनुरोध प्रस्तुत किए:
- i. मै. रेफेक्स इंडस्ट्रीज लि. (आयातक)
 - ii. मै. एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लि. (आयातक)
 - iii. मै. स्टालियन इंडिया फ्लुओरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
 - iv. मै. महिमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आयातक)
- ट. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई कि वे

सभी अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण भौतिक आवागमन के रोक के चलते सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी।

- ठ. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि(पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2016- 31 मार्च 2017- 1 अप्रैल 2017 - 31 मार्च 2018 - 1 अप्रैल 2018 - 31 मार्च 2019 और जांच की अवधि शामिल है।
- ड. प्राधिकारी ने जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु हेतु वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से सौदा-वार आयात आंकड़े प्राप्त किए और सौदों की आवश्यक जांच के पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया।
- ढ. घरेलू उद्योग द्वारा और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था।
- ण. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों(जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के लिए उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) ज्ञात की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने विडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए 30 जून, 2021 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक रूप में अपने विचार रखने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप में व्यक्त विचारों को और खंडों, यदि कोई हों, को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने अगोपनीय अनुरोध साझा किए और उन्हें खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- थ. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और सूचना पर इन जांच परिणामों में उनके साक्ष्यों द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने की सीमा तक विचार किया गया है।
- द. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जो अंतिम जांच परिणामों का आधार है, की सत्यता से संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का समझी गई सीमा तक सत्यापन किया।
- ध. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को यथा-आवश्यक ढंग से स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।
- न. नियमों के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 26 अगस्त, 2021 के प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से प्रकट किया गया था, और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया था, को इन अंतिम जांच परिणामों में संबोधित किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत सीमा तक विचार किया गया है और इस जांच परिणाम में उन पर ध्यान दिया गया है।
- प. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना जुटाने से मना किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

- फ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरुआत के समय विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:-

“3.वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद “हाइड्रोफ्लोराकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाईफ्लोरोमिथेन” है। आर-32 या डाईफ्लोरोमिथेन का रासायनिक सूत्र सीएच₂एफ₂ है और यह सीएस सं. 75-10-5 के रूप में पंजीकृत है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रियोन-32, मिथाइलीन डिफ्लोराइड, मिथाइलीन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हलोकार्बन आर-32, फ्लोरोकार्बन आर-32, और यूएन 3252 के रूप में भी जाना जाता है। एचएफसी घटक आर-32 का प्रयोग मुख्यतः आवासीय एअरकंडीशन प्रणालियों में होता है।

4.संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 में सीमा शुल्क उप शीर्ष संख्या 290339 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. हाइड्रोफ्लोराकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाईफ्लोरोमिथेन का रासायनिक सूत्र सीएच₂एफ₂ है और यह सीएस सं. 75-10-5 के रूप में पंजीकृत है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रियोन-32, मिथाइलीन डिफ्लोराइड, मिथाइलीन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हलोकार्बन आर-32, फ्लोरोकार्बन आर-32, और यूएन 3252 के रूप में भी जाना जाता है। एचएफसी घटक आर-32 का प्रयोग आवासीय एअरकंडीशन प्रणालियों में होता है।

ख. यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 290339 के तहत वर्गीकृत है।

ग. आवेदक ने आयातित उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

घ. घरेलू उद्योग को पीयूसी के पैकड और अनपैकड रूपों के लिए अलग-अलग मार्जिन परिकलित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और सामान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/उत्पादकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. पीयूसी के पैकड और अनपैकड रूपों की लागत और कीमत में 20-30 प्रतिशत का अंतर है। याचिका में पाटन और क्षति का दावा करते समय वस्तु के लिए ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। प्राधिकारी को इनकी तुलना अलग-अलग करनी चाहिए और अलग-अलग मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “हाइड्रोफ्लोराकार्बन घटक आर-32 या डाईफ्लोरोमिथेन” है।
8. हाइड्रोफ्लोराकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 या डाईफ्लोरोमिथेन का रासायनिक सूत्र सीएच₂एफ₂ है और यह सीएस सं. 75-10-5 के रूप में पंजीकृत है। इसे एचएफसी-32, एफसी-32, फ्रियोन-32, मिथाइलीन डिफ्लोराइड, मिथाइलीन फ्लोराइड, कार्बन फ्लोराइड हाइड्राइड, हलोकार्बन आर-32, फ्लोरोकार्बन आर-32, और यूएन 3252 के रूप में भी जाना जाता है। एचएफसी घटक आर-32 का प्रयोग आवासीय एअरकंडीशन प्रणालियों में होता है।

9. इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 290339 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।
10. पैकड और अनपैकड विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के तर्क के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी ने पैकड और अनपैकड रूपों के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किया है। पाटन और क्षति मार्जिन को पैकड और अनपैकड रूपों के लिए पाटन मार्जिनों के भारित औसत के रूप में निर्धारित किया गया है।
11. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और प्रयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग (डीआई) ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. आवेदक अर्थात् मै. एसआरएफ लिमिटेड का भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
 - ख. आवेदक ने संबद्ध देश से जांच अवधि में संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है।
 - ग. आवेदक संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निर्यातकों/उत्पादकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) ‘‘घरेलू उद्योग’’ का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ‘‘घरेलू उद्योग’’ पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’’

15. यह आवेदन मै. एसआरएफ लिमिटेड ने दायर किया है। आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि न तो उन्होंने जांच अवधि में संबद्ध देश से पीयूसी का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश में पीयूसी के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।
16. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह समझते हैं कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. याचिका का अगोपनीय अंश (एनसीवी) और अनुबंध क एडी नियमावली के नियम 7, व्यापार सूचनाओं 1/2013 और 10/2018 के अनुसार दायर किया गया है।

- ख. मिहामा इंडिया, स्टेलियन इंडिया और एमपीसीएल ने संगत विधिक प्रावधानों, प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं और सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए घरेलू उद्योग को अपने अनुरोधों का एनसीवी परिचालित नहीं किया है। उन्होंने सुनवाई में भी भाग नहीं लिया है। इन पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जाना चाहिए। एचआर जॉनसन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश पर भरोसा किया गया है।
- ग. अनेक प्रतिवादी पक्षकारों ने व्यापार संख्या 10/2018 के उल्लंघन में अपने संबंधित पक्षकार की सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।
- घ. सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक आधारों पर अत्यधिक गोपनीयता को अपनाया है। इससे घरेलू उद्योग के रक्षा का अधिकार बाधित होता है और स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।
- ड. एनआईपी व्यापार संवेदी सूचना है जिसका सारांश संभव नहीं है।
- च. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े तीसरे पक्ष के आंकड़े हैं जिन्हें प्रकट करने का प्राधिकार घरेलू उद्योग के पास नहीं है। इन्हें व्यापार सूचना 7/2018 का पालन करते हुए लिया गया है। चीन से 'पेट रेजिन' संबंधी पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को चयनित और अचयनित दोनों आंकड़े देने का घरेलू उद्योग का कोई दायित्व नहीं है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. +/- 10 प्रतिशत के विहित विपठन के अनुसार एनआईपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। गोपनीयता के दावे में दावा की गई एनआईपी का कोई तर्कसंगत अनुमान नहीं है।
- ख. प्राधिकारी ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं जिसकी गोपनीयता के दावे से प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हैं और याचिकाकर्ता इस सूचना को सार्वजनिक करने में अनिच्छुक हो।
- ग. अगोपनीय अंश गोपनीय अंश की अनुकृति नहीं है और इसलिए जांच समाप्त की जानी चाहिए। मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने बताया कि गोपनीय पाठ (सीवी) याचिका में एनसीवी की अनुकृति का कोई अर्थ नहीं है और उसने अपने अनुरोध इस प्रकार किए जैसे कि उसे अपनी पसंद के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने का अधिकार है और किसी भी मामले में उसने गोपनीय अंश की अनुकृति प्रदान नहीं की है।
- घ. याचिका के अगोपनीय अंश में नियमावली, संगत व्यापार सूचनाओं और हितबद्ध पक्षकारों के बचाव के अधिकार का अनुबंध-क (क्षति विवरण) और अनुबंध-4 (लागत संबंधी सूचना) के उत्तर में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करके उल्लेघन किया गया है।
- ड. याचिकाकर्ता यह दावा नहीं करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पेटेंट युक्त है और प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर उनका स्वामित्व है। यहां तक कि विनिर्माण प्रक्रिया के व्यापक विवरण को भी अस्पष्ट आधारों पर गोपनीय रखा गया है।
- च. घरेलू उद्योग ने किसी विधि-सम्मत कारण के बिना और नियम और प्राधिकारी की प्रक्रिया के उल्लंघन में काफी सूचना को गोपनीय रखा है। सामान्य मूल्य के मद-वार ब्यौरे, निर्यात कीमत के लिए समायोजन के साक्ष्य, लाभ/हानि और प्रतिशत रूप में नियोजित पूंजी पर कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन, कुल मांग में हिस्सा, मजदूरी के ब्यौरे गोपनीय रखे गए हैं।
- छ. प्रपत्र ए से एल तक कोई मूल सूचना दिए बिना पूरी तरह रिक्त छोड़ा गया है।
- ज. अनेक अन्य मापदंडों जैसे आरएंडडी व्यय, एकत्रित निधियों, निर्यात कीमत/इकाई प्रति यूनिट पीबीआईटी, पीयूसी की खरीद और एनआईपी की गणना में भी आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा करते हुए कोई कारण बताए बिना व्यापार सूचना का उल्लंघन किया है। इन मापदंडों संबंधी सूचना की अनदेखी की जानी चाहिए।

- झ. याचिकाकर्ता ने सौदा-वार आयात आंकड़े भी नहीं दिए हैं। एकजोटिक डेकोर संबंधी सेस्टेट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग ने संबंधित पक्षकारों के सौदों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ट. घरेलू उद्योग के अनुरोध के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित दलीलें दी हैं:
- i. घरेलू उद्योग का यह तर्क गलत है कि निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - ii. जिबो फेयुआन ने गोपनीय अंश में लागत, कीमत और भारत को निर्यात का पीबीआईटी प्रस्तुत किया है।
 - iii. घरेलू उद्योग की गोपनीयता संबंधी आपत्तियां प्रश्नावली के उत्तर की उचित समीक्षा के बिना की गई हैं। यद्यपि, निर्यातकों ने विनिर्माण प्रक्रिया के गोपनीय होने का दावा किया है, यही दावा घरेलू उद्योग ने भी किया है। गोपनीयता का दावा नियमावली के अंतर्गत कारण सहित अनुमति प्राप्त है जिस पर घरेलू उद्योग ने प्रश्न नहीं उठाया है।
 - iv. शेनडांग ने नियमावली के अनुसार गोपनीय अंश में संबंधित पक्षकारों की सूचना दी है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

20. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है (उदाहरण के लिए, उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या क्योंकि उसके प्रकटन से उसे देने वाले किसी व्यक्ति पर या उस व्यक्ति पर, जिससे यह सूचना ली गई है, पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा) या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दिया गया है और उचित कारण बताए गए हैं, ऐसी सूचना को प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाना चाहिए। ऐसी सूचना का प्रकटन उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
21. प्राधिकारी ने आवेदकों और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को सभी हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा था।
22. महिमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आयातक प्रश्नावली के उत्तर के संबंध में यह देखा गया है कि इन कंपनियों ने अगोपनीय अंश में

गोपनीय अनुरोधों का कोई सार्थक सारांश प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार किया है।

23. डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में निर्यातक देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य से संबंधित आंकड़ों को हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। यह भी नोट किया गया है कि कोई हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से स्वतंत्र रूप से आंकड़े ले सकता है और इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अपना प्रति-दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी मानते हैं कि आयात आंकड़े शेयर करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया व्यापार सूचना 07/2018 दिनांक 15 मार्च, 2018 में निर्धारित है। इसमें व्यवस्था है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा अपनाए गए चयनित आयात आंकड़े हार्ड कॉपी में शेयर किए जा सकते हैं और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस से आयात सौदा आंकड़ों द्वारा अपरिष्कृत सौदों के लिए प्राधिकारी से प्राधिकार मांग सकते हैं। कोविड-19 के कारण चयनित आयात आंकड़ों की स्कैन्ड प्रति विहित प्रपत्र के अनुसार घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह प्रक्रिया अब सभी पक्षकारों और जांचों के लिए संगत, एकसमान रूप से लागू की जा रही है और इसमें हितबद्ध पक्षकारों को उनके हितों की रक्षा का पर्याप्त अवसर दिया गया है।
24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के दोनों समूहों ने समान सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है और फिर भी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसी सूचना के गोपनीयता के दावे पर ध्यान दिलाया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूप से दावा की गई सूचना की सामान्यतः गोपनीय आधार पर अनुमति है। चूंकि प्राधिकारी ने पूर्व में ऐसी सूचना पर गोपनीयता की अनुमति दी है, इसलिए वर्तमान मामले में भी इसकी अनुमति दी गई है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:-

- क. चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर अधूरा है क्योंकि इसमें संबद्ध पक्षकारों के प्रश्नावली के उत्तर शामिल नहीं हैं। प्रतिवादी कंपनियों के सभी संबंधित पक्षकारों ने यूएस में हुई जांच में उत्तर दिया है। तथापि, इनमें से कुछ पक्षकारों ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों के अनुसार पीयूसी से संबंधित सभी कंपनियों और पीयूसी का निर्यात कर रहे असंबंधित निर्यातकों को प्रश्नावली का उत्तर देना चाहिए। यदि ऐसे संबंधित पक्षकार सहयोग नहीं करते हैं, तो प्रतिवादी पक्षकार को भी असहयोगी माना जाना चाहिए।
- ख. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से पीयूसी से संबंधित सिनोकैम लैनलियन, झेजियांग सनमेई, और शानडोंग डोंगयुई के कतिपय संबंधी पक्षकार असहयोगी हैं क्योंकि इन पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अनुचित व्यापार भेद-भाव का समाधान करना है जो भारत में उद्योग के लिए क्षतिकारी है। इससे समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा स्थापित होती है, व्यापार विकृतियां समाप्त होती हैं और उचित प्रतिस्पर्धा संभव होती है। इससे घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट का समाधान होता है और अंतिम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे उत्पाद के आयात या उसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उत्पादन से आपूर्ति की विश्वसनीयता की गारंटी मिलती है।
- घ. उपभोक्ताओं और आयातकों द्वारा भागीदारी बिल्कुल न्यूनतम है। भारत में किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता एसोसिएशन ने एडीडी लागू करने का विरोध नहीं किया है। इससे पता चलता है कि उन्हें जांच के परिणामस्वरूप किसी प्रतिकूल प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है चूंकि अंतिम उत्पाद पर पीयूसी की लागत काफी कम है इसलिए अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- ड. एसआरएफ द्वारा उत्पादित उत्पादों की संख्या पर विचार करते हुए कंपनी ने एडीडी लागू करने के लिए प्राधिकारी से बार-बार संपर्क नहीं किया है, यह दर्शाता है कि आवेदक एक जिम्मेदार और उचित कंपनी है।
- च. आवेदक द्वारा पीयूसी के उत्पादन का आरंभ प्रधान मंत्री की आत्म निर्भर भारत पहल की तर्ज पर है। व्यापक तौर पर संबद्ध वस्तु का मजबूत प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन होना जनहित में होता है। यदि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहती है तो उपभोक्ता पूर्णतः विदेशी उत्पादकों पर निर्भर हो जाएंगे।
- छ. घरेलू उद्योग ने 11 महीने के आंकड़े दिए हैं क्योंकि मार्च, 2020 के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े फाइलिंग के समय उपलब्ध नहीं थे।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने पूरी जांच अवधि के बजाए केवल 11 महीने के आयात आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। चूंकि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े और चयनित आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दिए गए हैं, इसलिए घरेलू उद्योग के लिए आयात आंकड़ों में छेड़छाड़ करना बहुत सरल हो जाता है।
- ख. केवल 11 महीनों के आंकड़ों का प्रयोग करके आयात कीमत की गलत गणना से पाटन मार्जिन की गलत गणना हुई है। अतः याचिका अविश्वसनीय है और उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को मार्च, 2020 तक के आंकड़ों को शामिल करने के लिए संशोधित याचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- ग. आर 134ए संबद्ध पाटनरोधी और एसएसआर जांच और एचएफसी ब्लैंड्स के आयातों से संबंधी पाटनरोधी जांच दर्शाती है कि याचिकाकर्ता चीन के उत्पादकों और निर्यातकों पर हमला करने, लाभ अधिकता करने और एकाधिकारी लाभ प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों से प्राधिकारी से अनावश्यक संरक्षण मांगता रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग पीओआई के दौरान अपनी लागत में अत्यधिक वृद्धि की भरपाई के लिए व्यापार उपचार का एक कार्यनीतिक निर्णय के रूप में प्रयोग करता है, इसकी जांच की जानी चाहिए।
- ड. चूंकि एसआरएफ एकमात्र उत्पादक है, इसलिए गुणवत्ता पर विचार किए बिना पूरे बाजार की आपूर्ति केवल उनके द्वारा की जाएगी और वे संभावित प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश पर बाधा लगाकर बाजार शक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार, प्रतिस्पर्धी माहौल और भारत में उद्योग के स्वस्थ विकास को नुकसान पहुंचाता है। कीमत की अधिकता और कीमत विभेद की 100 प्रतिशत संभावना है।
- च. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 दर्शाती है कि उपभोक्ताओं की 13 प्रतिशत शिकायतें फ्लोरोकेमिकल व्यवसाय में थी, जिसमें एचएफसी आर-32 शामिल हैं और यह दर्शाता है कि उत्पाद खराब गुणवत्ता का है और इस प्रकार वे गुणवत्ता ग्रेडों और विचाराधीन उत्पाद के विशिष्ट ग्रेडों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।
- छ. पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा जो ऐसे मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी कच्ची सामग्री पर निर्भर हैं जो अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हों। इससे आजीविका का भारी नुकसान एमएसएमई द्वारा निर्यात में कमी विनिर्माताओं और खराब गुणवत्ता की वस्तुओं की सीमित उपलब्धता के बीच बाजार असमानता उत्पन्न होगी। पीयूसी के उत्पादन की याचिकाकर्ता की क्षमता सीमित है। भारत में प्रयोक्ता उच्च मांग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयात पसंद करते हैं।
- ज. एडीडी लागू होने से भारत में उपभोक्ताओं के लिए एसी के विकल्प भी सीमित हो जाएंगे क्योंकि सरकार ने पहले ही भारत में रेफ्रिजरेट के साथ एसी का आयात प्रतिबंधित कर दिया है। एडीडी से याचिकाकर्ता का एकाधिकार मजबूत होगा और प्रभुत्व का दुरुपयोग होगा। याचिकाकर्ता विधिसंमत प्रतिस्पर्धा से अपने निवेश को बचाने और अपने एकाधिकार को मजबूत करने के लिए एडीडी की मांग कर रहा है।

- झ. पीयूसी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध उपायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक डाउनस्ट्रीम उत्पादक घटक गैस के रूप में पीयूसी की ओर जा रहे हैं। इसलिए एडीडी लागू होने से वहनीय उपलब्धता प्रभावित होगी जिससे उच्चतर ग्लोबल वार्मिंग आशंका (जीडब्ल्यूपी) वाली गैसों जैसे आर-410 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। पीयूसी में आर-410ए की तुलना में अनेक अन्तर्निहित लाभ हैं। इसलिए, पीयूसी की वहनीयता जनहित में भी महत्वपूर्ण है।
- ञ. शुल्क, यदि कोई हो, लगाने से पहले जनहित पर विचार किया जाना चाहिए। एडीडी लगने से डाउनस्ट्रीम उद्योग और छोटे अंतिम प्रयोक्ताओं की आजीविका में नुकसान होगा, मांग और आपूर्ति में अंतर बढ़ेगा, एमएसएमई में तैयार सामान के निर्यात में कमी आएगी और विनिर्माताओं के बीच बाजार असमानता बढ़ेगी। जन हित शुल्क लागू नहीं करने के पक्ष में है।
- ट. संबद्ध वस्तु प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती है। एडीडी लगने से रेफ्रिजेंट के इस समूह के आयातों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रभावित होगी चूंकि भारत में अधिकांश एसी अब पीयूसी का प्रयोग करते हैं और उसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए एडीडी लगने से प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा।
- ठ. पीयूसी सर्वाधिक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण अनुकूल और व्यावहारिक रूप से सुविधाजनक रेफ्रिजेंट गैस है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने विरोधी पक्षकारों और घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर निम्नानुसार विचार किया है:

- क. प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकारों की सूचना की जांच की है और सुनिश्चित किया है कि संबद्ध वस्तु से संबंधित सभी पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा यथा-अधिदेशित अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की हो।
- ख. प्रयोक्ता उद्योग पर एडीडी के प्रभाव संबंधी तर्क के बारे में यह नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतें कैसे उपभोक्ताओं को प्रतिकूलतः प्रभावित करती हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए सूचना प्रस्तुत की है कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली होगा। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत कम होती है और इससे अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए यह मानते हुए कि 1 टन क्षमता का कोई एअरकंडीशनर लगभग 40,000 रु. में आता है, तो एचएफसी घटक आर-32 जो एअरकंडीशनर में प्रयुक्त है, की मात्रा एक किलोग्राम से कम होगी। यह मानते हुए कि एचएफसी घटक आर-32 की लागत लगभग 200 रुपए है, अंतिम उत्पाद के अंतिम प्रयोक्ता पर विचाराधीन उत्पाद की लागत बिल्कुल मामूली होगी।
- ग. इस प्रकार यह नोट किया गया है कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना सहित प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित एडीडी का प्रभाव सिद्ध नहीं किया है, फिर भी यदि यह माना जाए कि एडीडी लगने से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं, तो भी अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बिल्कुल मामूली होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेष रूप से तब जब कि एडीडी की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की प्रक्रिया द्वारा अर्जित अनुचित लाभों को समाप्त करना है, घरेलू उद्योग की क्षति को रोकना है और उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद करना है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उनकी याचिका में केवल 11 महीने के आंकड़े प्रयोग करने के संबंध में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के अपने आकलन में पूरी पीओआई के लिए आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, परिणामस्वरूप वर्तमान निर्धारण में पाटन मार्जिन और क्षति मापदंड लिए गए हैं।
- ड. घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक संरक्षण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित विधिक अपेक्षाएं पूरी होती हों। इसके अलावा, किसी

उत्पाद विशेष पर शुल्क लगाए जाने या बढ़ाए जाने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि वह 71 उत्पादों के उत्पादन में शामिल है और वर्तमान में 4 उत्पादों में एडीडी द्वारा संरक्षित है। इसके अलावा, चीन से नाइलोन टायर कोड फैब्रिक और मिथाइलीन क्लोराइड के आयातों पर पहले से लागू एडीडी अब प्रभावी नहीं है।

- च. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार सृजित होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी का चीन, यूएस, भारत और जापान में वैश्विक रूप से उत्पादन होता है। यह उत्पाद मुक्त श्रेणी में है और इसलिए विभिन्न देशों से मुक्त रूप से आयातित किया जा सकता है। पाटनरोधी उपाय लगने से चीन से आयात किसी तरह प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाम करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल हो सके जो देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा, एकाधिकार और प्रतिस्पर्धारोधी उपायों के आरोपों की जांच के लिए एक अलग संस्थान है।

छ. पाटन का आकलन – पद्धति और मापदंड

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. प्राधिकारी को सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध 1 के पैरा 1-6 का पालन केवल तभी करना चाहिए यदि प्रतिवादी चीनी कंपनियां यह सिद्ध करें कि उनकी लागत और कीमत सूचना ऐसी है जिसके अनुसार अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।
- ख. चूंकि चीन के उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के पात्र नहीं हैं। इसलिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनबंध 1 के पैरा 7 का पालन किया जाए।
- ग. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के समय चीन को एनएमई के रूप में माना है। क्योंकि किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का प्रदर्शन या दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य को निर्यातक की घरेलू बिक्री कीमत या लागत के आधार पर परिकलित नहीं किया जाना चाहिए। यह एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 पर आधारित होना चाहिए। जांच शुरुआत अधिसूचना वाले आधार का ही पालन किया जाना चाहिए।
- घ. चीन को एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के अनुसार एनएमई माना जाता है। अनुच्छेद 15(क)(ii) 11 दिसंबर, 2016 को ही समाप्त हुआ है। अनुच्छेद 15(क)(i) अब भी लागू है इसलिए चीन की घरेलू कीमतों या लागतों को केवल तभी अपनाया जा सकता है यदि उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं की मौजूदगी दर्शा सकते हों। वर्तमान मामले में वे ऐसा करने में विफल रहे हैं। ईयू-फास्टनर्स में अपीलिय निकाय की समुक्तियां विचारणीय हैं। प्राधिकारी ने हाल की सभी जांचों में चीन को एनएमई माना है। चीन से 'इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर्स' के आयातों संबंधी एसएसआर जांच के अंतिम जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है। अन्य जांच परिणामों में भी यही मत अपनाया गया है।
- ड. सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- च. आवेदक ने विधिवत् रूप से समायोजित भारत में देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। संबद्ध देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु आवेदक ने विधिवत् रूप से समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत ली है और उसने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़ा है।

- छ. आवेदक ने सीआईएफ कीमत ली है और निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, बैंक प्रभार और वैट के लिए उसमें समायोजन किए हैं।
- ज. पाटन मार्जिन न केवल काफी अधिक है बल्कि संबद्ध देश के लिए बहुत अधिक है।
- झ. भागीदारी नहीं करने को त्रुटिपूर्ण माना जाना चाहिए। असहयोग पर उपलब्ध तथ्य लागू किया जाना चाहिए।
- ञ. असंबंधित असहयोगी निर्यातकों के ज़रिए निर्यात वाले उत्पादकों के लिए प्राधिकारी से ऐसे निर्यातकों के ज़रिए निर्यातों का हिस्सा निर्धारित करने का अनुरोध है। यदि हिस्सा अधिक न हो तो प्रतिवादी उत्पादक को असहयोगी माना जाना चाहिए। प्रचालन प्रथाओं संबंधी नियम पुस्तिका के पैरा 16.26 पर भरोसा किया जाए, यदि वे निर्धारित सीमा से कम हों तो सभी बिक्रियों के लिए निर्यात कीमत परिकलित की जानी चाहिए और प्रतिकूल तथ्य लागू किए जाने चाहिए।
- ट. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए समायोजन प्राधिकारी की प्रक्रिया के संगत हैं। घरेलू उद्योग को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर उसकी सत्यता और पर्याप्तता के अधीन निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, चूंकि किसी ने भी एनएमई का दावा नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित होगा।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- क. निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन को प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त वास्तविक आंकड़ों के अनुसार निर्धारित होना चाहिए।
- ख. डब्ल्यूटीओ में चीन के शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल के अनुसार पाटनरोधी कार्यवाही में प्रतिनिधि देश की प्रक्रिया 11 दिसंबर, 2016 से बहु-पक्षीय विधिक आधार की दृष्टि से अभावग्रस्त होनी चाहिए। प्रतिनिधि देश की पद्धति चीन को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानने पर विचार नहीं करते हुए इस मामले में सामान्य मूल्य के परिकलन में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए। भारत के पास गैर बाजार अर्थव्यवस्था के प्रयोग से सामान्य मूल्य के परिकलन का कोई आधार नहीं है। संदर्भ: ईयू – फास्टनर्स जिसमें यह बताया गया था कि प्रोटोकॉल के 15(क) और 15(ख) के बीच संबंध की व्याख्या प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 के समाप्त होने पर चीन को स्वतः रूप से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने को उचित ठहराता है।
- ग. चीन को इस बात के मद्देनजर पाटनरोधी जांच के लिए किसी अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्य के रूप में माना जाना चाहिए कि यूएस और ईयू ने इस बात को हाल ही में माना है। प्राधिकारी से चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने, एडीए के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करने और सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु इस उत्तर की लागत और कीमतों के आंकड़े अपनाने का अनुरोध किया जाता है और इस जांच में प्रतिनिधि देश के आंकड़े अपनाए नहीं जाने चाहिए।
- घ. घरेलू उद्योग ने एडी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से सामान्य मूल्य परिकलित किया है। संदर्भ: शेनटांग मात्सुशिता में उच्चतम न्यायालय का निर्णय – अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है। घरेलू उद्योग द्वारा ईष्टम क्षमता का प्रयोग नहीं करने पर सामान्य मूल्य अधिक हो गया है।
- ड. यद्यपि चीन के उत्पादकों द्वारा एक असंबंधित निर्यातक के ज़रिए निर्यात किए गए थे, तथापि सहयोगी निर्यातक के ज़रिए निर्यातों का हिस्सा अलग मार्जिन निर्धारण की सीमा से अधिक है। किसी असंबंधित पक्षकार द्वारा असहयोग को सहयोगी पक्षकारों के विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए।
- च. मूल कच्ची सामग्री कीमत (फ्लोरस्पायर) में वृद्धि संबंधी याचिकाकर्ता के दावे की जांच की जानी चाहिए। पाटन मार्जिन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक उच्च संख्याओं का प्रयोग हुआ है, जिनका कोई आधार नहीं है।

- छ. आवेदक ने निर्यात कीमत की गणना हेतु समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन, बैंक प्रभारों और चीन के निर्यातकों द्वारा प्रदत्त वैट पर की गई कटौतियों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। समुद्री बीमा संबंधी कटौतियां काफी अधिक हैं और उन्हें अस्वीकृत किया जाए। निर्यातक के उत्तर से इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।
- ज. पैकड और अनपैकड रूपों की अलग अलग तुलना की जानी चाहिए।
- झ. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन मार्जिन के दावे परिकल्पित सामान्य मूल्य को बढ़ाए जाने का परिणाम है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ख) बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्भूत वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह देने हुए प्रश्नावलियां भेजीं कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में सहयोग किया है।

- i. मै. झेजियांग क्यूझोऊ जुक्सिन फ्लुओराइन केमिकल कं. लि.
- ii. मै. झेजियांग सनमेई केमिकल्स इन्ड. कं. लि.
- iii. मै. जिबो फेइयुआन केमिकल कं. लि.
- iv. मै. शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि.
- v. मै. झेजियांग क्यूहुआ फ्लुओर-केमिस्ट्री कं. लि.
- vi. मै. फुजियान क्विंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं. लि.
- vii. जियांग्सु सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.
- viii. मै. ताइजिंग मेइलान न्यू मैटिरियल्स कं. लि.
- ix. ताइझोऊ क्विंगसोंग रेफ्रिजरेट न्यू मैटिरियल कं. लि.
- x. मै. सिनोकेम लानतियान फ्लुओरो मैटिरियल्स कं. लि.
- xi. मै. ताइकिंग मेइलान झिंगलान न्यू मैटिरियल्स कं. लि.

चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

32. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:

“क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

33. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अधीन प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली के प्रदत्त सूचना/आंकड़ों के ज़रिए नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंडों को पूरा किया जाना अपेक्षित है। क्योंकि चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों ने विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है इसलिए सामान्य मूल्य के परिकलन को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

34. संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण

35. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 का पाठ निम्नानुसार है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले उचित तीसरे देश ने उत्पाद की कीमतें या परिकलित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमतें आवेदक या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और किसी सार्वजनिक स्रोत से यह प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर उचित देश का चयन करना अपेक्षित है। यह भी नोट किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं दी है जिसे प्राधिकारी द्वारा अपनाया जा सके। इस प्रकार, प्राधिकारी की राय है कि एकमात्र उपलब्ध विकल्प समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ जोड़कर भारत में ईष्टम उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक)

37. मै. शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि. ने विहित प्रपत्र और ढंग से प्रश्नावली का उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। पीओआई के दौरान मै शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि ने अनपैकड रूप में भारत को ***यूएस डॉलर मूल्य की ***एमटी पीयूसी का सीधे निर्यात किया है। मै शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन और पत्तन तथा अन्य संबंधित व्ययों के लिए समायोजन का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा परिकलित मै शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं. लि के लिए कारखानाद्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं., लि. (उत्पादक) और झेजियांग कुहुआ फ्लुओर-केमिस्ट्री कं. लि., (निर्यातक)

38. झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कं., लि. (“जुक्सिन”) और झेजियांग कुहुआ फ्लुओर-केमिस्ट्री कं. लि., (कुहुआ), चीन जन.गण. के कंपनी कानून के अधीन शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनियां हैं। जुक्सिन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का उत्पादक है और उसने कुहुआ के जरिए असंबंधित भारतीय ग्राहकों को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। दोनों कंपनियों ने अपेक्षित प्रश्नावली प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान जुक्सिन ने कुहुआ के जरिए अनपैकड रूप में भारत में असंबंधित ग्राहकों को ***यूएस डॉलर मूल्य की ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। जुक्सिन और कुहुआ ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्ययों, बैंक प्रभारों और ऋण लागत के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। प्राधिकारी द्वारा परिकलित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

जियांग्सु सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि.(उत्पादक), फुजियान किंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं., लि.(उत्पादक) और झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड.कं. लि., (संबंधित निर्यातक)

39. मै.जियांग्सु सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. और मै. फुजियान किंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं., लि. जो चीन में संबद्ध वस्तु के दो संबंधित उत्पादक हैं, ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इन दोनों संबंधित उत्पादकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु एक संबंधित निर्यातक अर्थात् मै. झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. के जरिए भारत को निर्यात की गई है। सभी तीन कंपनियों के उत्तर विहित प्रपत्र में हैं और इसलिए भारत को निर्यात की श्रृंखला पूरी है। उत्तर से यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. ने भारत को ***एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है, जिसमें से ***एमटी मैं फुजियान किंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं., लि. द्वारा उत्पादित थी और शेष ***एमटी जियांग्सु सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. द्वारा उत्पादित थी। यह दावा किया गया है कि ये सामग्रियां केवल अनपैकड रूप में निर्यातित हैं। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय परिवहन, समुद्री बीमा के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा इस समूह के लिए परिकलित निवल कारखानाद्वारा निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

जिबो फेइयुआन केमिकल कं., लि. (उत्पादक/निर्यातक)

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं जिबो फेइयुआन केमिकल कं., लि. – चीन ने इस जांच में उत्तर दिया है और निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की है। पीओआई के दौरान कंपनी ने अनपैकड रूप में भारत को ***यूएसडॉलर मूल्य की ***एमटी का सीधे निर्यात किया है। निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और संभलाई प्रभार, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है, जिनकी प्राधिकारी ने अनुमति दी है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा इस कंपनी के लिए परिकलित निवल कारखानाद्वारा निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

मै. ताइजिंग मेइलान न्यू मैटिरियल्स कं., लि. और ताईझोऊ क्यूंगसोंग रेफ्रिजरेट न्यू मैटिरियल कं., लि. (उत्पादक); मै. सिनोचेम फ्लुओरो मैटिरियल्स कं., लि. (निर्यातक/व्यापारी) और मै. तईजिंग मेइलान झोंगलान न्यू मैटिरियल्स कं., लि.(घरेलू विक्रेता), चीन जन.गण.

41. पीओआई के दौरान, मै. ताइजिंग मेइलान न्यू मैटिरियल्स कं., लि. और ताईझोऊ क्यूंगसोंग रेफ्रिजरेट न्यू मैटिरियल कं., लि. (उत्पादक) ने अनपैकड रूप में हनीवेल ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. के जरिए भारत को ***यूएसडॉलर मूल्य की ***एमटी पीयूसी का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि मै. ताइजिंग मेइलान न्यू मैटिरियल्स कं., लि. की एक संबंधित कंपनी मै. सिनोकेम फ्लुओरो मैटिरियल्स कं., लि. ने भारत को ***यूएसडॉलर मूल्य की ***एमटी पीयूसी का सीधे निर्यात किया है। तथापि हनीवेल ट्रेडिंग (शंघाई) कं. लि. ने प्राधिकारी के समक्ष निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि काफी निर्यातों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार नहीं करते हैं। अतः उत्पादक को असहयोगी माना गया है।

चीन जन.गण. से असहयोगी निर्यातक

42. चीन जन.गण. से अन्य (असहयोगी) निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत की गणना नियमावली के नियम 6(9) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर की गई है। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस में यथा-दर्ज आयातों और उत्पादकों तथा निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार किया है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

43. यह नोट किया गया है कि अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया रही है कि वह पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु संबंधित निर्यातक उत्पादकों और निर्यातकों पर एक एकल कंपनी के रूप में विचार करें और इस प्रकार उनके लिए एकल पाटन मार्जिन निर्धारित करें। अतः सभी संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को एक एकल कंपनी माना गया है और एकल पाटन मार्जिन दिया गया है, जिसे इन सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर परिकलित किया गया था।

44. ऊपर यथा परिकलित संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:-

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक	सीएनवी (यूएसडा./एमटी)	एनईपी (यूएसडा./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडा./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज%)
1.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं., लि..	***	***	***	***	50-60
2.	झेजियांग क्यूझोऊ जुक्सिन फ्लोराइन केमिकल कं., लि. द्वारा झेजियांग क्यूहुआ फ्लोर- केमिस्ट्री कं., लि. के जरिए निर्यातित	***	***	***	***	70-80
3	जियांगसु सनमेई केमिकल इन्ड. कं., लि. और फुजियान क्यूइंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं. लि; झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. के जरिए निर्यातित	***	***	***	***	70-80
4.	मै. जिबो फेइयुआन केमिकल कं., लि.	***	***	***	***	60-70
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	90-100

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त क्षति संबंधी सूचना केवल संबद्ध वस्तु से संबंधित है। आंकड़ों को मानकीकृत किया गया है क्योंकि नए संयंत्र के कारण क्षमता उपयोग आधार वर्ष में बहुत कम था। घरेलू उद्योग ने अधिकतम क्षमता उपयोग/अनुमानित क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। फिर भी, अधिकांश मापदंडों में गिरावट आई है।
- ख. एडी नियमावली के नियम 11(2) में प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग हेतु क्षति निर्धारित करना अपेक्षित है, जिसका नियम 2(ख) के अंतर्गत अर्थ "समग्र रूप से" घरेलू उत्पादक हैं। संयंत्र-वार आकलन की अनुमति नहीं है।
- ग. संबद्ध देश से आयात, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों का 100 प्रतिशत हैं। इससे अन्य देशों के उत्पादकों द्वारा चीन के उत्पादकों से प्रस्तावित कीमतों की बराबरी न कर पाने का पता चलता है। ऐसा उच्च क्षमताओं के बिना संभव नहीं हो सकता है। संबद्ध आयातों में क्षति अवधि में समग्र रूप से तथा सापेक्ष रूप से भारी वृद्धि हुई है।

- घ. संबद्ध आयातों की आयात कीमत में पीओआई के दौरान भारी गिरावट आई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती, ह्रास और न्यूनीकरण कर रहे हैं। पहुंच कीमत 2017-18 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लागत से कम रही हैं। कीमत कटौती और सकारात्मक क्षति मार्जिन यह निर्धारित करने के एक कारक हैं कि क्या पाटन आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ड. कानून में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है जिसमें याचिका स्तर पर कम कीमत पर बिक्री या क्षति मार्जिन संबंधी सूचना प्रदान की जाए।
- च. चार वर्ष की क्षति अवधि का उद्देश्य संपूर्ण अवधि का आकलन करना है क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि से थोड़ा पहले उत्पादन शुरू किया है, इसलिए स्वाभाविक है कि आधार वर्ष में कार्य-निष्पादन कमजोर रहा है।
- छ. पीओआई में क्षमता विस्तार बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने और संबद्ध वस्तु के संबंध में भारत को आत्म-निर्भर बनाने की घरेलू उद्योग की दीर्घावधिक प्रतिबद्धता का परिणाम है। पुराने संयंत्र से काफी बिक्रियां हुई हैं। ब्याज लागत में वृद्धि जो कुल लागत का मामूली हिस्सा है, से क्षति आंकड़े प्रभावित नहीं हुए हैं।
- ज. घरेलू क्षमता से अधिक मांग आयात को उचित ठहराती है न कि पाटन को। आयातों की मात्रा पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें निर्धारित करते समय आयात कीमतों का पालन करने को बाध्य होना पड़ा है।
- झ. घरेलू उद्योग ने प्रतिकूल मात्रात्मक प्रभाव और काफी अधिक कीमत क्षति झेली है। डीएसएम इदेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के निर्णय और चीन से “कास्मैटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पिग्मेंट्स” संबंधी पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है।
- ञ. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में पीओआई में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग 2018-19 के बाद अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है, जो पाटन संबद्ध आयातों के अभाव में 67 प्रतिशत हो गया होता। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा संबद्ध आयातों के मुकाबले काफी कम है। घरेलू उद्योग की मालसूची में पीओआई में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू बिक्री और मालसूची के बीच अनुपात में पीओआई में भारी गिरावट आई है, जो पाटन का प्रभाव दर्शाती है।
- ट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि में गिरावट आई है। पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई की दृष्टि से पीओआई में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पीओआई में घाटा उठाना पड़ा है। लगभग सभी क्षति मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक है। पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता भी कमजोर पड़ गई है।
- ठ. चीन के पास काफी अधिक अतिरिक्त क्षमता है जो सभी प्रमुख बाजारों की मांग पूरी करने हेतु पर्याप्त है। चीन में संबद्ध वस्तु के उत्पादक निर्यात बाजारों पर काफी अधिक निर्भर है। तथापि, एडीडी लागू होने के कारण यूएस का बाजार उनके लिए बंद है। यूएस द्वारा चीन से संबद्ध वस्तु पर एडीडी लागू करने से पता चलता है कि चीन के उत्पादक न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं। लागू शुल्क की राशि चीन के उत्पादकों द्वारा भारी पाटन दर्शाती है।
- ड. प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तरों का विश्लेषण दर्शाता है कि उन्होंने उपलब्ध अतिरिक्त क्षमताओं के बावजूद अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है। फ्लोस्पार की कीमतों में वृद्धि के बावजूद संबद्ध आयात की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि संबद्ध आयातों की लागत और कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों के आधार पर तय नहीं होती हैं। प्रतिवादियों ने सूचना का स्रोत बताए बिना ईष्ट चाइना फ्लोस्पार की कीमतों पर भरोसा किया है और वह चीन में कीमतें नहीं दर्शाती है। इससे चीन के एनएमई दर्जे का भी पता चलता है। प्रतिवादियों ने इस तथ्य पर प्रश्न नहीं उठाया है कि फ्लोस्पार की कीमतों में वृद्धि के बावजूद पहुंच कीमत में गिरावट आई है।

- ढ. संबद्ध पाटित आयातों के कारण, कीमत कटौती से घरेलू बाजार में कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता इतनी अधिक घट गई है कि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत वसूली करने में असमर्थ रहा था। लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह तथ्य कि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, दर्शाता है कि क्षति घरेलू उद्योग की उत्पादकता के कारण नहीं हुई है।
- ण. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में व्यापार खंड का उल्लेख है जिसमें पीयूसी और अन्य उत्पाद शामिल हैं। वार्षिक रिपोर्ट समग्र रूप से कंपनी के बारे में है और केवल पीयूसी के घरेलू कार्य-निष्पादन के बारे में नहीं है। दाहेज संयंत्र का 8 दिन के लिए बंद होना घरेलू उद्योग की समग्र गिरावट का कारण नहीं हो सकता है। अन्य सार्वजनिक विवरण भी घरेलू उद्योग की क्षति के कारण को नहीं बदलते हैं। प्रतिवादियों ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग का उत्पाद घटिया है। दाहेज संयंत्र ने अगस्त, 2019 में उत्पादन शुरू किया और इसलिए बाढ़ के प्रभाव का तर्क वास्तव में गलत है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

46. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. क्षति विश्लेषण के लिए उत्पाद के संकीर्णतम समूह/रेंज के चयन के लिए घरेलू उद्योग ने कोई पद्धति नहीं बताई है। प्राधिकारी को पीयूसी और अन्य उत्पादों के बीच घरेलू उद्योग द्वारा लागत आबंटन का विस्तृत सत्यापन करना चाहिए।
- ख. अनुबंध 2.2 और प्रपत्र IV-ए के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादन संबंधी सूचना में कोई संगतता नहीं है। याचिकाकर्ता को यह स्पष्ट करने का निदेश किया जाना चाहिए कि प्रपत्र-एच के आंकड़ों को मानकीकृत क्यों नहीं किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में काफी अच्छा कार्य-निष्पादन किया है और उसे कोई क्षति नहीं हुई है। पाटन और पहुंच कीमत में गिरावट संबंधी घरेलू उद्योग के दावों का कोई अर्थ नहीं है, जब उन्हें भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों और कथित पाटन के बीच घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में देखा जाए। पहुंच कीमत में गिरावट कार्यवाही योग्य नहीं है। चीन के लिए आयात की प्रवृत्ति अतिरिक्त क्षमता का दबाव नहीं दर्शाती है। आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने कीमत कटौती के काफी अधिक होने के समय बाजार हिस्से को बनाए रखा है।
- घ. संबद्ध आयातों में वृद्धि को मांग में वृद्धि तथा 2016-17 में ही घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन आरंभ करने के आलोक में देखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वृद्धि आयात मात्रा में वृद्धि से काफी अधिक है, इससे बाजार हिस्से पर कब्जा हुआ है। संबद्ध आयातों में केवल मांग के अनुरूप वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले पीओआई में पहुंच कीमत में गिरावट 2020 में एचएफसी बाजार में वृद्धि अर्थात् वैश्विक मांग में वृद्धि के कारण हुई थी। आयात कीमतों को इस पृष्ठभूमि में देखा जाए।
- ड. घरेलू उद्योग की क्षमता में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। यदि घरेलू उद्योग के पास 2016-17 से 2018-19 तक घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी तो डाउनस्ट्रीम उद्योग के पास संबद्ध वस्तु का आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और संबद्ध आयातों ने घरेलू बिक्रियों की जगह नहीं ली होती। याचिका में यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग ने भारी कीमत कटौती के बावजूद अपने बाजार हिस्से और लाभप्रदता में वृद्धि कैसे की।
- च. पीबीआईटी, नकद लाभ, और आरओसी ने पीओआई में भारी वृद्धि देखी गई है। पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले पीओआई में लाभप्रदता में गिरावट का कोई आधार नहीं है क्योंकि आधार वर्ष की तुलना में काफी वृद्धि हुई थी। आधार वर्ष में असामान्य लाभों में पीओआई में केवल वृद्धि ही हुई है।
- छ. पीओआई में क्षमता उपयोग में केवल तभी गिरावट आई है जब क्षमता में वृद्धि हुई थी। आरओसी के उसी वर्ष में वृद्धि की आशा करना अतर्कसंगत होगा जिसमें क्षमता में वृद्धि हुई है। उत्पादकता में पूरी

क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। औसत नियोजित पूंजी और नियोजित पूंजी पर आय में जांच अवधि में जबरदस्त वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या, मजदूरी वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। केवल सकारात्मक कीमत कटौती, संबद्ध निर्यात के लिए क्षति मार्जिन की मौजूदगी का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को क्षति उठानी पड़ी है। कम कीमत पर बिक्री का दावा नहीं करके याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है। अतः कमतर शुल्क नियम के अनुसार और क्षति मार्जिन के नकारात्मक होने पर जांच समाप्त कर दी जानी चाहिए।

- ज. घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज लागत, मूल्यहास लागत, मजदूरी और अन्य ऊपरी व्ययों में वृद्धि हुई है जिससे क्षति हुई है। असामान्य रूप से उच्च मूल्यहास और वित्त प्रभावों के ज़रिए कारणात्मक संबंध की विफलता से 400 श्रृंखला स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर रक्षोपाय जांच में घाटे पाए गए थे। वर्तमान मामले में, समान तथ्य देखे गए हैं। उत्पादन लागत और क्षति मापदंडों का अलग-अलग संयंत्र-वार आकलन वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए आवश्यक है।
- झ. मालसूची में वृद्धि उत्पादन मात्रा, स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण हुई है। *ब्रिज स्टोन टायर मैनुफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* मामले में सेस्टेट के आदेश पर भरोसा किया गया है जिसमें मालसूची में वृद्धि और बिक्री में वृद्धि के बीच संबंध पर चर्चा हुई थी। वर्तमान मामले में, बिक्री मात्रा के साथ मालसूची में वृद्धि हुई है। मालसूची को उत्पादन मात्रा और न कि समग्र मात्रा के संबंध में देखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में कोई सापेक्ष वृद्धि नहीं हुई है।
- ञ. एसआरएफ लिमिटेड के केमिकल खंड का पीबीआईटी दर्शाता है कि याचिकाकर्ता 2016 से निरंतर लाभ कमा रहा है, जो मार्च, 2020 में सर्वाधिक था। चूंकि फ्लोरोकेमिकल्स के लिए कोई अलग सूचना नहीं दी गई है, इसलिए यह माना जाता है कि केमिकल खंड में फ्लोरोकेमिकल्स और विशेष रसायन दोनों शामिल हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 में कोविड-19 के कारण दाहेज संयंत्र के अस्थायी रूप से बंद होने का उल्लेख है, जिसका याचिकाकर्ता ने याचिका में उल्लेख नहीं किया है। घरेलू उद्योग को क्षति वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख के अनुसार ऑटो और व्हाइट गुड्स क्षेत्र में लंबी और काफी बुरी मंदी के कारण हुई है। याचिकाकर्ता की क्षमता उपयोग में संबद्ध आयातों में वृद्धि के बावजूद वृद्धि हुई है। यह रूझान याचिकाकर्ता के पैमाने की किफायतों में वृद्धि दर्शाता है। याचिकाकर्ता द्वारा उसके निवेशकों के साथ बताई गई आय के अनुसार पीओआई में उनका क्षमता उपयोग 70-75 प्रतिशत है, जो उद्योग के लिए ईष्टम है।
- ट. आयात कीमत/कीमत कटौती तथा लाभप्रदता के बीच सह-संबंध का अभाव भी है। दाहेज में बाढ़ के कारण अगस्त, 2019 में दाहेज संयंत्र का प्रचालन प्रभावित हुआ और लागत बढ़ गई। पीयूसी उत्पादन की याचिकाकर्ता की क्षमता सीमित है। घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी पुरानी है, इसकी वजह से पैमाने की किफायतें कम रही हैं और उत्पादन की लागत अधिक रही है।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा इस तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि चीन के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग ने बाजार के आकर्षक होने पर विचार नहीं किया है। अतिरिक्त क्षमता की गणना की पद्धति त्रुटिपूर्ण है। अधिशेष का परिकलन सभी बाजारों में उत्पाद की खपत घटाकर किया जाता है और न कि केवल घरेलू बाजार में। यह आरोप भी अवास्तविक है क्योंकि सूचना का स्रोत नहीं बताया गया है। यह मूल जांच से संगत नहीं है। अधिशेष क्षमता की समझ त्रुटिपूर्ण है और आंकड़े निराधार हैं। घरेलू उद्योग को अतिरिक्त क्षमताओं को भारत भेजने की संभावना सिद्ध करनी चाहिए। जैसाकि इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माना गया था, केवल अतिरिक्त क्षमताओं को घरेलू उद्योग को क्षति के प्रत्याशित और आसन्न खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। चीन से निर्यात या अधिक क्षमता या क्षमता में वृद्धि का आवश्यक अर्थ पाटन नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में कोई ठोस बात नहीं रखी गई है।
- ड. घरेलू उद्योग ने फ्लोरस्फार की कीमतों संबंधी सूचना का स्रोत नहीं बताया है। घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई वृद्धि दर गलत है क्योंकि फ्लोरस्फार से हाइड्रोजन फ्लोराइड के उत्पादन में दो उप उत्पाद, उत्पादित होते हैं, इसलिए स्फोरस्फार की कीमतों में परिवर्तन संबद्ध वस्तु की कीमतों को सीधे प्रभावित

नहीं करता है। फ्लोरस्पार और संबद्ध वस्तु की कीमतों की स्थिति घरेलू उद्योग की स्थिति के समान है। घरेलू उद्योग ने स्वयं नहीं बताया है कि वह कच्ची सामग्री के रूप में फ्लोरस्पार का प्रयोग करता है। संबद्ध वस्तु की कीमतें अधिक महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों, बाजार प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य मामलों द्वारा प्रभावित होती है।

- ढ. यूएस द्वारा एडीडी लागू किया जाना वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं है। घरेलू उद्योग की स्वयं परिवर्चना हेतु जांच हुई थी। इसलिए, घरेलू उद्योग इस तर्क पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। यूएस में एडीडी लागू होने से भारत में आयातों में वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ा है। आयात भारत में मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए किए गए हैं।
- ण. याचिकाकर्ता ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि तीसरे देशों के आयात की अनुपस्थिति चीन की कीमतों से मुकाबला करने में असमर्थता के कारण है। पीयूसी एक नया उत्पाद है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरा है तथा जिसे चीन के उत्पादकों ने तीसरे देशों के उत्पादकों से अलग वरीयता दी है। भारत में आयातक भी आपूर्ति के विश्वसनीय होने के कारण चीन के आयातों को पसंद करते हैं। घरेलू उद्योग भारत में रिफिलरों के लिए आपूर्ति नहीं करता है।
- त. घरेलू उद्योग ने अनेक व्ययों (विज्ञापन, अन्य प्रशासनिक व्यय, अन्य बिक्री और वितरण व्यय, बिक्री पर कमीशन, बिक्री पर छूट/रिबेट, बाहरी मालभाड़ा और निर्यात संबंधी व्यय) का दावा किया है जिन पर एडी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार विचार नहीं किया जाना चाहिए। एनआईपी पर कारखानाद्वारा स्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

47. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है। नीचे प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का वस्तुतः समाधान किया गया है।
48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।
49. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य कारणों की वजह से हुई है और घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के विवरणों के अनुसार कोई क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः स्पष्ट है।
50. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग /स्पष्ट खपत का आकलन

51. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारत में मांग या उत्पाद की स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है।

भारत में मांग	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3429	7494	10235
संबद्ध देश से आयात - चीन	एमटी	634	1,974	3,810	5,503
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	311	601	868
अन्य देशों से आयात	एमटी	-	-	-	-
भारतीय मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	393	782	1113

52. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात और संबद्ध वस्तु की मांग में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की खपत आवासीय एअरकंडीशनिंग में होती है और घरेलू उद्योग ने बताया है कि घरेलू एसी उत्पादन में काफी तेजी आने का अनुमान है और भारत में एअरकंडीनर(एसी) बाजार में भारी वृद्धि के कारण और एचसीएफसी 22 तथा एचएफसी 32 और एचएफसी 410 ए के प्रतिस्थापन सहित अगले दशक में एचएफसी की जबरदस्त वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा, पीओआई में स्थापित उत्पाद के लिए वर्तमान मांग के मुकाबले पीओआई के अंत में घरेलू उद्योग की क्षमता ***एमटी थी। घरेलू उद्योग ने अब संबद्ध वस्तु सहित विभिन्न फ्लोरोकेमिकल्स के संबंध में आगे और क्षमता विस्तार की घोषण की है और अब इसने क्षमता में और विस्तार करने का निर्णय लिया है।

ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा

53. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत की दृष्टि से भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
संबद्ध देश- चीन	एमटी	634	1,974	3,810	5,503
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	311	601	868
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	100	100	100	100
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	110	142
खपत	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	77	78

54. यह नोट किया गया है कि:

- क. संबद्ध देश से आयात की मात्रा में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। यह वृद्धि सतत और काफी अधिक है।
- ख. संबद्ध आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 100 प्रतिशत बनते हैं।
- ग. संबद्ध आयातों में भारतीय उत्पादन की दृष्टि से 2017-18 में गिरावट आई परंतु तत्पश्चात् 2018-19 और पीओआई में वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. क्षति अवधि के दौरान आयात कीमता में वृद्धि

माह	दर (रु/एमटी)
2016-17	1,70,236
2017-18	2,00,019
2018-19	2,34,355
अप्रैल'19	1,79,410
मई'19	1,71,542
जून'19	1,70,841
जुलाई'19	1,68,412
अगस्त'19	1,67,745
सितं.'19	1,69,991
अक्तू.'19	1,76,855
नव.'19	1,45,214
दिस.'19	1,46,086
जन.'20	1,35,687
फर.'20	1,37,294
मार्च'20	1,38,952

ख. कीमत कटौती

56. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना चीन से आयातों के पहुंच मूल्य से साथ की गई है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के मद्देनजर और पैकड तथा अनपैकड उत्पाद की लागत में भारी अंतर को देखते हुए पैकड और अनपैकड रूपों के लिए कीमत कटौती की गणना अलग-अलग की है।

कीमत कटौती- पीओआई	यूनिट	कुल	अनपैकड	पैकड
निवल बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***
पहुंच कीमत (संबद्ध देश चीन)	₹/एमटी	1,66,629	1,66,431	2,36,244
कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
	रेंज	40-50	40-50	80-90

57. यह नोट किया गया है कि चीन के आयात पैकड और अनपैकड दोनों रूपों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ख. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

58. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में बदलावों की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्री लागत- घरेलू	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	72	81
बिक्री कीमत - घरेलू	₹/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	66	60
पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,83,387	2,15,471	2,53,690	1,66,629
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	138	91

59. यह नोट किया गया है कि:

क. यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की लागत में गिरावट से अधिक है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

ख. जांच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है। परिणामस्वरूप यद्यपि लागत में वृद्धि हुई है तथापि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

60. यह नोट किया गया है कि संबद्ध आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

61. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जिनमें बिक्रियों, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है:

62. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	154
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	545	611
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	545	396
नए संयंत्र में परीक्षण उत्पादन सहित उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	545	662

64. यह नोट किया गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग पहले भिवाड़ी संयंत्र में एचएफसी घटक का विनिर्माण कर रहा था। कंपनी ने 2016-17, जो वर्तमान जांच में क्षति अवधि का आधार वर्ष है, में इस उत्पाद का उत्पादन शुरू किया। इस संयंत्र की क्षमता ***एमटी है।
- ख. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और बताया है कि ऐसा देश में उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग के मद्देनजर किया गया था। तथापि, दाहेज में क्षमता विस्तार किया गया है। इसके अलावा, यद्यपि भिवाड़ी संयंत्र की क्षमता ***एमटी थी। तथापि दाहेज संयंत्र को ***एमटी की क्षमता के साथ स्थापित किया गया है और इसने नवंबर, 2019 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- ग. नवंबर, 2019 में दाहेज में उत्पादन की शुरुआत के साथ घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने भिवाड़ी में उत्पादन रोक दिया। अतः पीओआई के लिए अनुपातिक उत्पादन ***एमटी के रूप में लिया गया है।
- घ. चूंकि कंपनी ने भिवाड़ी संयंत्र में मार्च, 2016 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, इसलिए 2016-17 में उत्पादन काफी कम था और तत्पश्चात् इसमें वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस संयंत्र का क्षमता उपयोग भी 2016-17 में कम था और तत्पश्चात् 2018-19 तक बढ़ा। तथापि, जांच अवधि में क्षमता उपयोग में पुनः गिरावट आई।
- ङ. यद्यपि उत्पादन में क्षति अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई है, तथापि उपयोग में पीओआई में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग की 2016-17 में बिक्री मात्रा बहुत कम (व्यवहार्यतः नगण्य) थी और उत्पादन का अधिकांशतः आबद्ध रूप से उपभोग किया गया या निर्यात हुआ अथवा भंडार में पड़ा रहा। तत्पश्चात् जांच अवधि तक बिक्री मात्रा में भारी वृद्धि हुई थी।
- छ. घरेलू उद्योग ने उत्पादन के एक हिस्से की आबद्ध रूप से खपत की।

II. मांग में बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	894	982	941
चीन जन.गण.	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	77	78
कुल	%	100	100	100	100

66. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 2018-19 तक बढ़ा है और तत्पश्चात् पीओआई के दौरान इसमें गिरावट आई है। संबद्ध देश के बाजार हिस्से में पूरी क्षति अवधि में गिरावट आई और पीओआई में मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि और पीओआई में उच्च स्तर पर बना रहा है।

III. मालसूची

67. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	एमटी	-	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	100	76	127
अंतिम स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	76	100	256
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	176	383

68. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में पूरी क्षति में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग स्टॉक में 35 दिनों की मालसूची रख रहा है, जो उत्पाद की भारी मांग पर विचार करते हुए काफी अधिक है।

IV. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय नीचे तालिका में दी गई है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के मद्देनजर की लाभ में गिरावट ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण हुई है, लाभप्रदता की जांच भी ब्याज और मूल्यहास से पहले लाभ पर विचार करते हुए की गई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	46	-14
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	2131	3501	(***)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	340	365	128
आय और मूल्यहास पूर्व लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	345	382	158
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	269	242	-52

70. यह नोट किया गया है कि:

- क. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता में गिरावट आई है। पीओआई में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।
- ख. चूंकि घरेलू उद्योग ने 2016-17(संयंत्र की शुरुआत के बाद) में काफी कम मात्रा का उत्पादन किया है और क्षति अवधि में बिक्री में वृद्धि हुई है, इसलिए कर-पूर्व लाभ में 2018-19 तक वृद्धि हुई है। तथापि, कर-पूर्व लाभ में पीओआई में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है।
- ग. नकद लाभ में आधार वर्ष की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। यद्यपि क्षति अवधि में प्रति यूनिट लाभ में तेजी से गिरावट आई है, तथापि घरेलू बिक्रियों पर अर्जित सकल लाभ में 2018-19 तक वृद्धि हुई है।
- घ. निवेश पर आय में 2017-18 में वृद्धि हुई है, परंतु आधार वर्ष के मुकाबले गिरावट आई है। इसके अलावा, पीओआई में आरओआई नकारात्मक था। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में ब्याज पश्चात लाभ के संबंध में गिरावट आई है।
- ड. प्राधिकारी ने लाभ, नकद लाभ और आरओआई में इतनी भारी गिरावट के कारणों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि यद्यपि कुछ मामूली गिरावट के लिए ब्याज और मूल्यहास लागत में वृद्धि उत्तरदायी हो सकती है, परंतु, लाभ, नकद लाभ और आरओआई में गिरावट प्राथमिक रूप से बिक्री कीमत में गिरावट के कारण हुई है।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
बिक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	66	60
उत्पादन लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	72	81
लाभ/हानि	रु./एमटी	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	61	46	(14)
मूल्यहास	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	21	39
ब्याज	रु./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	71	86

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
मजदूरियां	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	684	1444	3117
रोजगार	संख्या	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	175	400	1238
प्रति यूनिट मजदूरी	र./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	151	265	510
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	161	95	94
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	454	545	611

72. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की मजदूरी, उत्पादकता और कर्मचारियों की संख्या में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया गया है कि ऐसा पहले 2016 में भिवाड़ी में नया उत्पादन शुरू करने के परिणामस्वरूप हुआ और तत्पश्चात 2019 में दाहेज में नए उत्पादन के कारण हुआ। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने केवल इतनी सूचना दी है जो उनके पीयूसी संयंत्र से संबंधित है। इसमें आबद्ध निविष्टियां शामिल हैं। तथापि घरेलू उद्योग ने रोजगार शामिल नहीं किया है। किसी भी तरह से घरेलू उद्योग ने इसके लिए क्षति का दावा नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव नहीं दर्शाते हैं।

vi. वृद्धि

73. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में सकारात्मक थी और कीमत मापदंडों के संबंध में नकारात्मक थी। इसके अलावा, मात्रात्मक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि, प्राधिकारी द्वारा माने गए इष्टम स्तरों से कम थी।

विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
उत्पादन	वर्ष/वर्ष%	-	354	20	12
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/वर्ष%	-	3413	118	37
बिक्री की लागत	वर्ष/वर्ष%	-	2017	160	55
बिक्री कीमत	वर्ष/वर्ष%	-	-40	9	-9
लाभ/हानि	वर्ष/वर्ष%	-	2031	64	-143
आरओसीई	वर्ष/वर्ष%	-	169	-10	-122

vii. क्षति मार्जिन की मात्रा

74. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक होती है जहां तक भारत में आयात पाटित हुए हैं। जांच से पता चला है कि पाटन मार्जिन क्षति अवधि में सकारात्मक और काफी अधिक रहा है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि यूएस प्राधिकारियों ने भारत की तुलना में चीन से यूएसए को उच्चतर निर्यात कीमत के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के संबंध में 221 प्रतिशत का पाटन मार्जिन निर्धारित किया है।

Viii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

75. घरेलू उद्योग ने इस आधार पर किसी क्षति का दावा नहीं किया है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है। निवेश संबंधी निर्णय क्षति अवधि के दौरान केवल किसी उत्पाद विशेष के कार्य-निष्पादन पर आधारित नहीं हो सकते हैं और उस उत्पाद के दीर्घावधि भविष्य द्वारा शासित होते हैं।

VIII. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद का एकमात्र घरेलू आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा, यद्यपि यूएस और जापान में काफी उत्पादन होता है (जैसा घरेलू उद्योग ने बताया है) तथापि, केवल चीन से उत्पाद का आयात हुआ है। इसके अलावा, यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत 2018-19 तक बढ़ी है, पीओआई में इसमें भारी गिरावट आई। इसके अलावा, इस अवधि और पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में भी भारी गिरावट आई है। इस प्रकार यह देखा गया है कि आयात कीमतों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें सीधे प्रभावित हो रही हैं। यह भी देखा गया है कि संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य पीओआई में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि वह आयात की कम कीमतों के कारण, वर्तमान कीमतों को बनाए रखने में सक्षम नहीं था और परिणामस्वरूप, आयातों में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग को हुआ कीमत ह्रास या न्यूनीकरण आयातों की कम कीमतों के कारण हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात हैं।

IX. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन की मात्रा

77. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित कार्यकारी लेखाकार द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित सूचना/आंकड़ों की विस्तृत जांच के बाद किया गया है। क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति + औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति दी गई थी क्योंकि नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित क्षति रहित कीमत पर कर-पूर्व लाभ की अनुमति है और उसका पालन किया गया है। उत्पाद के खुले और पैकड रूप के लिए अलग-अलग एनआईपी निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु विचार किया गया है।
78. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अपनाई गई सीआईएफ निर्यात कीमत से निर्धारित की गई है। आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित करने हेतु लागू सीमा शुल्क जोड़ा गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
79. ऊपर यथा-निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों हेतु क्षति मार्जिन परिकलित किया गया है और नीचे तालिका में दिया गया है। चूंकि निर्यातकों ने उत्पाद को अनपैकड रूप में निर्यात किया है, इसलिए घरेलू उद्योग की एनआईपी पर तदनुसार विचार किया गया है।

क्र.सं.	उत्पादक	क्षति रहित कीमत (यूएसडा./एमटी)	पहुंच कीमत (यूएसडा./एमटी)	क्षति मार्जिन (यूएसडा./एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज%)
1.	शानडोंग डोंगयुई केमिकल कं., लि..	***	***	***	***	60-70
2.	झेजियांग क्यूझोऊ जुक्सिन फ्लोराइन केमिकल कं., लि. द्वारा झेजियांग क्यूहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री कं., लि. के ज़रिए निर्यातित	***	***	***	***	80-90

3	जियांग्सु सनमेई केमिकल इन्ड. कं., लि. और फुजियान क्यूइंगलियु डोंगयिंग केमिकल इन्ड. कं. लि; झेजियांग सनमेई केमिकल इन्ड. कं. लि. के जरिए निर्यातित	***	***	***	***	70-80
4.	मै. जिबो फेइयुआन केमिकल कं., लि.	***	***	***	***	60-70
5.	अन्य सभी	***	***	***	***	90-100

ज.3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

80. यह नोट किया गया है कि:

- संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।
- संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं।
- क्षमता उपयोग में भारी गिरावट आई है और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग घाटा, नकद घाटा और निवेशों पर नकारात्मक आय झेल रहा है।

पूर्वोक्त के मद्देनजर यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

झ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

81. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी ज्ञात कारकों की जांच की है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दिया है और निम्नानुसार नोट किया है:

क) पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

82. चीन जन.गण. से आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का 100 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसा कोई अन्य देश नहीं है जिसने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया हो।

ख) मांग में संकुचन

83. संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति अवधि और पीओआई के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। वास्तव में, देश में उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग पर विचार करते हुए, कंपनी ने उत्पादन क्षमताओं के आगे और विस्तार की घोषणा की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए पूर्णतः समर्थ है। तथापि, घरेलू उद्योग को पाटित कीमतों पर आयातों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है।

ग.) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

84. विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई वास्तविक प्रतिकूल बदलाव नहीं हुआ है, बजाए इसके खपत की प्रवृत्ति में उत्पाद के पक्ष में सुधार हुआ है, जैसा कि देश में बढ़ी हुई खपत से स्पष्ट है। घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच में हुई क्षति खपत की प्रवृत्ति में किसी प्रतिकूल परिवर्तन के कारण नहीं हो सकती है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थिति या ऐसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं का पता नहीं चला है, जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हों। पीयूसी भारत में केवल एक कंपनी द्वारा उत्पादित है और केवल एक देश द्वारा निर्यातित है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

86. किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी खास बदलाव की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया गया है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने 2016 में पहला संयंत्र और अगस्त, 2019 में दूसरा संयंत्र स्थापित किया है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

87. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। अतः निर्यात कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

छ) अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

88. घरेलू उद्योग ने पीयूसी संबंधी क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ उन्हें अपनाया गया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

89. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को अन्य कारकों की वजह से पीओआई में क्षति नहीं हुई है। इसके अलावा, निम्नलिखित कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध पाटित आयातों के कारण हुई है:

- क. पीयूसी की आयात कीमत में 2016-17 से 2018-19 के बीच वृद्धि हुई है। तथापि, आयात कीमत में पीओआई में तेजी से गिरावट आई है और यह आधार वर्ष में प्रचलित स्तरों से भी कम थी। आयात कीमत में तेजी से गिरावट के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2018-19 में वृद्धि हुई और बाद में पीओआई में गिरावट आई। जहां तक 2016-17 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री मात्रा काफी कम थी और यह घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक रूप से आरंभिक कीमत थी। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में पीओआई में आयातों की पहुंच कीमतों में 34 प्रतिशत की गिरावट आई थी। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की कीमतें घट गईं तथापि, घरेलू उद्योग ने कीमतों में केवल 9 प्रतिशत तक की कमी की और वह पहले ही बिक्री लागत से कम थी।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा कीमत घटाने के बावजूद, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं। आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है बल्कि पीओआई में उत्पादन लागत से भी कम है।
- ग. पाटित आयातों के कारण बाजार में उत्पाद की कीमतों पर अत्यधिक ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ रहा है।
- घ. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव से लाभप्रदता में भारी गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में भी भारी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पीओआई में वित्तीय घाटे, नकद घाटे और नकारात्मक आय का सामना करना पड़ रहा है।
- ड. घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक आर्थिक मापदंडों के संबंध में नकारात्मक हो गई है।

90. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

अ. प्रकटन पश्चात अनुरोध

अ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

91. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं: उत्तर

- क. मिहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड और एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की अनदेखी की जानी चाहिए क्योंकि वे कोई अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।
- ख. घरेलू उद्योग के मानक कार्यनिष्पादन पर विचार किया जाना चाहिए जो वास्तविक क्षमता उपयोग पर विचार करने के बजाय घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाता है।
- ग. परिकलित सामान्य मूल्य के संबंध में, जहां भी आबद्ध निविष्टियाँ शामिल हैं, आबद्ध निविष्टियों में उचित लाभ जोड़ा जाना है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल की कीमत को भी अपनाया जा सकता है।
- घ. पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है और पर्याप्त है।
- ङ. किसी भी उपयोगकर्ता या ओईएम या उपयोगकर्ता संघों ने कोई भी सत्यापन योग्य जानकारी नहीं दी है, यह दर्शाता है कि उन पर कोई अत्यधिक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- च. शुल्कों को लगाने से उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा, हुई क्षति का निवारण किया जा सकेगा और घरेलू उत्पादक को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम बनाया जा सकेगा, और इसलिए यह उपभोक्ताओं और व्यापक रूप से जनता के हित में होगा।
- छ. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो उद्योग को और अधिक क्षति का सामना करना पड़ेगा और अंततः वह समाप्त हो जाएगा, जिससे चीन के उत्पादकों को अधिक लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को उनकी दया पर आश्रित रहना होगा। यदि उपभोक्ताओं को आयातित सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उन्हें उच्च स्तर की मालसूची बनाए रखनी होगी, जबकि घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, धारित मालसूची को बहुत निचले स्तर पर रखा जा सकता है।
- ज. भारत की समय सीमा से पहले ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चीन के दायित्वों ने चीन को विचाराधीन उत्पाद को पाटित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया है ताकि चरणबद्ध ढंग से कटौती की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक उच्च आधार रेखा का निर्माण किया जा सके।
- झ. घरेलू उद्योग ने मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि की है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक क्षमताएं स्थापित करने की भी योजना बनाई है।
- ञ. पाटनरोधी शुल्क न केवल घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करेगा बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से आयात को भी प्रोत्साहित करेगा, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- ट. शुल्क लगाना भी भारत सरकार की नीति के अनुरूप है क्योंकि केंद्र सरकार विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से देश में एयर कंडीशनर के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे रही है।
- ठ. घरेलू उद्योग द्वारा निवेश में वृद्धि से अधिक रोजगार ही मिलेगा, जिससे समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा, देश के लिए वर्ष 2032 में एचएफसी की चरणबद्ध समाप्ति शुरू होने से पहले व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प होना रणनीतिक महत्व का है, जो तभी संभव होगा जब उद्योग को पाटन से बचाया जाए।
- ड. अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ देश के भीतर विकास को संतुलित करना समग्र रूप से देश के हित में है। घरेलू एचएफसी उद्योग का संरक्षण करने में विफलता एसी विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में एक कमजोर कड़ी छोड़ देगी और चीन के निर्माताओं द्वारा इसका फायदा उठाए जाने की संभावना है।

- ढ. स्वदेशी विनिर्माण बाजार में उत्पाद की कीमत स्थिरता, निर्बाध आपूर्ति, एक विश्वसनीय भागीदार पर निर्भरता, आयात प्रतिस्थापन, कम विदेशी व्यापार जोखिम, डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- ण. बढ़ते व्यापार घाटे और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण, घरेलू उत्पादन क्षमताओं पर अधिक भरोसा करना और आयात निर्भरता को कम करना महत्वपूर्ण है।
- त. घरेलू उद्योग बैकवार्ड एकीकृत है और उसने विचाराधीन उत्पाद में भारी निवेश किया है। इसलिए, आबद्ध निविष्टि में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन किया गया है।
- थ. चूंकि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इसका खुलासा किया जाना चाहिए।
- द. प्राधिकारी को भाग लेने वाले निर्यातकों को भेजे गए पत्र के अगोपनीय संस्करण और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के बाद, उत्तर, यदि कोई हो, और सत्यापन रिपोर्ट का प्रकटन करना चाहिए।

अ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- क. सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय चीन के कंपनियों के विवरण की अनदेखी करना चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (ii) के प्रावधानों को निष्प्रभावी कर देगा। प्रतिवादी कंपनी के लिए सामान्य मूल्य उनके द्वारा प्रस्तुत लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से दर्शाती हैं। चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के प्रस्तावित निर्धारण के संबंध में कोई विवरण प्रकट नहीं किया गया है या उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- ख. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति के संबंध में दिए गए बयानों को क्षति की वस्तुनिष्ठ जांच के बिना उनके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग को कैसे कथित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, इससे संबंधित अनुरोध को प्रकटन विवरण में शामिल या उसका विश्लेषण नहीं किया गया है।
- ग. इन कारकों के लिए जानकारी को छिपाने के लिए याचिका की तुलना में ब्याज और लागत के मूल्यहास के आंकड़े मीट्रिक टन के अनुसार दिए गए हैं।
- घ. प्रकटन विवरण में गैर- आरोपण विश्लेषण पर प्रस्तुतियों पर जांच या विश्लेषण के अभाव से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षति कथित आयातों के कारण नहीं बल्कि अन्य कारकों के प्रभाव के कारण हुई है। कथित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ङ. जांच अवधि की विभिन्न तिमाहियों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों के तिमाही विश्लेषण के आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया जाना चाहिए। पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए त्रैमासिक विश्लेषण चीन जनवादी गणराज्य से विस्कोस स्टेपल फाइबर पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में किया गया था। अंतिम दो तिमाहियों में जब कीमतों में भारी गिरावट आई थी तब प्रतिवादियों ने पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया था।
- च. खपत के संबंध में आयात में गिरावट आई है, इसलिए चीन जन. गण. से आयात में वृद्धि की दर वास्तव में मांग में वृद्धि की दर से काफी कम है। प्राधिकारी ने उत्पादन, बिक्री मात्रा, क्षमता और क्षमता उपयोग सहित क्षति मानकों में सुधार की प्रवृत्ति को नोट नहीं किया है।
- छ. जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी में गिरावट अप्रासंगिक है और उस पर किया गया अवलोकन आर्थिक मानकों का वस्तुपरक मूल्यांकन नहीं है।
- ज. जांच की अवधि के दौरान भिवाड़ी संयंत्र के बंद होने की सूचना हितबद्ध पक्षकारों को नहीं दी गई जिससे परिवर्तन और क्षति पर प्रभाव पर टिप्पणी करने का अवसर सीमित हो गया। नए संयंत्र के प्रारंभ होने और पुराने संयंत्र को बंद करने के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में उच्च लागत आई है और इसके लिए कथित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

- झ. प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जांच की अवधि के लिए उत्पादन जैसे आर्थिक मानकों को निर्धारित करने के लिए वास्तविक आंकड़े लिए गए हैं।
- ञ. एनआईपी के लिए जांच की अवधि में बिक्री की बढ़ी हुई लागत के प्रभाव की अनदेखी की जानी चाहिए। व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार प्रत्येक पीसीएन के लिए एनआईपी का प्रकटन रेंज में किया जाना है।
- ट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट क्षमता विस्तार और इसके परिणामस्वरूप वित्त लागत और ब्याज लागत में वृद्धि के कारण हुई है और प्राधिकारी ने पिछले मामलों में इस संबंध में शुल्क लागू करने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया है। दाहेज में उत्पादन सामान्य होने के बाद घरेलू उद्योग फिर से लाभदायक हो जाएगा। मूल्यह्रास में कुल वृद्धि और ब्याज लागत में कुल वृद्धि को विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए।
- ठ. प्रति इकाई मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि पर सूचना की सत्यता प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- ड. जांच की अवधि में घटी हुई आयात कीमत प्रतिवादी द्वारा क्षति जांच अवधि के दौरान बिक्री की लागत में लगातार कमी के कारण है। प्रतिवादियों द्वारा जांच की अवधि में पाटन में वृद्धि नहीं की गई है।
- ढ. याचिका में प्रदान की गई और प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी द्वारा प्रकट की गई लाभप्रदता मानकों से संबंधित जानकारी में महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले क्षति संबंधी अनुरोध याचिका के आधार पर किए गए हैं।
- ण. यद्यपि संबद्ध वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है, परंतु यह दर घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि की तुलना में काफी कम है और इसलिए कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है। उत्पादकता में गिरावट यह दर्शाती है कि क्षति अकुशल कार्यबल प्रबंधन के कारण हुई है।
- त. सिनोकेम समूह द्वारा दायर पूर्ण प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करना पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 5 का उल्लंघन है। किंगसोंग, जो कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है, की निर्यात कीमत को हनीवेल को बिक्री कीमत के रूप में निर्धारित किया जाना है, जो पहला स्वतंत्र क्रेता है, भले ही क्रेता कहीं भी स्थित हो।
- थ. हनीवेल एक असंबंधित क्रेता है और किंगसोंग पर जांच में उनकी सहायता न करने पर अधिक बोझ लगाकर और इस आधार पर उनकी प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है बल्कि मनमानी और पूर्व मामलों और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का उल्लंघन है। सिनोकेम ग्रुप ने बिक्री सौदों की जानकारी देने समय कानून द्वारा आवश्यक सभी शर्तों को पूरा किया है।
- द. किंगसोंग विचाराधीन उत्पाद का निर्यातक है और हनीवेल को वाणिज्यिक बीजक जारी करता है और चीन के सीमा शुल्क के लिए निर्यात घोषणा के लिए भी जिम्मेदार है।
- ध. यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्यात कीमत के व्यवहार पर भरोसा किया गया है, जहां निर्यात मूल्य का निर्धारण पहले स्वतंत्र क्रेता को बिक्री कीमत द्वारा किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहयोगी निर्यातक के निर्यात डेटा को मूल्य श्रृंखला के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- न. पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग और भारत में अंतिम उपयोगकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- प. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत काफी अधिक है। निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों के अनुसार करना होता है।

- फ. विचाराधीन उत्पाद के पैकड और अनपैकड रूपों के लिए अलग-अलग विक्षेपण के साथ पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए बल्क-से-बल्क की तुलना की जानी चाहिए।
- ब. शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप एकाधिकार बाजार बन जाएगा क्योंकि याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और बाद में जनहित प्रभावित होगा और भारत में उद्योग के विकास में बाधा आएगी।
- भ. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कैसे संबद्ध वस्तुओं की कीमतों ने उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। एसी में विचाराधीन उत्पाद को भरने की प्रक्रिया एक बार की प्रक्रिया नहीं है और इसे कई बार करने की आवश्यकता होती है। शुल्क लगाना उपभोक्ता के हित में या भारत सरकार के पर्यावरण उद्देश्यों के हित में नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के लिए खुदरा बाजार लागत संवेदनशील है।
- म. याचिकाकर्ता ने अपने हाल के क्षमता विस्तार और निवेश को चीन के आयातों से वैध प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए शुल्क संरक्षण की मांग की है। संबद्ध वस्तुओं की मांग बढ़ रही है जिसे अकेले घरेलू उद्योग द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है।
- य. संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि को विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग आपूर्ति अंतर के आलोक में देखा जाना चाहिए। मांग के संबंध में आयातों की मात्रा में गिरावट आई क्योंकि घरेलू बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, यह दर्शाता है कि संबद्ध आयात याचिकाकर्ता के विकास के लिए खतरा नहीं हैं।
- र. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के एक हिस्से का आबद्ध रूप से उपभोग किया है जो देश में उपयोगकर्ताओं और आयातकों को चीन से आयात पर निर्भर रहने के लिए छोड़ देता है और याचिकाकर्ता की अविश्वसनीयता को दर्शाता है।
- ल. याचिका में उच्च लाभप्रदता मानकों और प्राधिकारी द्वारा विचार की गई कम लाभप्रदता के बीच अंतर में विसंगति का कोई कारण नहीं बताया गया है। जांच की अवधि के लिए कुल लाभ/हानि के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया है।
- व. प्राधिकारी द्वारा की गई समुक्ति के विपरीत क्षति अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जांच की अवधि के दौरान वित्तीय कार्यनिष्पादन में गिरावट प्रचालन मानकों में गिरावट के कारण आई है।
- श. याचिकाकर्ता के दावे के विपरीत, मजदूरी, रोजगार और उत्पादकता जैसे आर्थिक मापदंडों संबंधी कार्यनिष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक है।
- ष. प्रतिवादी जैसे रिफिलरों को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति करने से याचिकाकर्ता का इनकार व्यावसायिक रूप से प्रतिबंधात्मक और एक अनुचित व्यापार प्रथा है।
- स. प्राधिकारी से अनुरोध है कि एचएफसी के उत्पादन और खपत के उचित नियंत्रण की अनुमति देने के लिए एचएफसी के फेस-डाउन के लिए राष्ट्रीय रणनीति को ध्यान में रखते हुए, शुल्क, यदि लगाया गया, तो उसकी अवधि न्यूनतम अवधि तक सीमित होनी चाहिए ताकि मध्य-2024 तक किगाली संशोधन के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।
- ह. मिहामा जापान में अपनी मूल कंपनी से विचाराधीन उत्पाद का आयात करती है, जिसके कारण भारतीय बाजार में बिक्री के लिए पहले से ही महंगे उत्पाद की कीमत अधिक हो जाती है।
- क्ष. चूंकि मिहामा के पास विनिर्माण और पुनः पैकेजिंग का लाइसेंस नहीं है, इसलिए इसके लिए ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के उपयोग से विचाराधीन उत्पाद की कुल लागत बढ़ जाएगी।
- त्र. जापान में मिहामा की मूल कंपनी ने भारत में सहायक कंपनी की स्थापना की है क्योंकि भारत सरकार विभिन्न एफटीए के तहत जापानी संस्थाओं का पक्ष लेती है और प्रचालन स्थापित करने और विस्तार करने की दृष्टि से भारत में भारी निवेश करती है। एडीडी लगाने से कंपनी द्वारा और अधिक निवेश में बाधा उत्पन्न होगी।

- ज. याचिकाकर्ता क्षति के अभाव में कई गुना बढ़ गया है जैसा कि उनके प्रचालन संबंधी नकदी प्रवाह विवरण से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता का ग्राहक आधार विदेशी निर्यातकों और आयातकों से बेहतर है। एडीडी लगाने से याचिकाकर्ता की बाजार हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 90% हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप मूल्य विनियमन और एकाधिकार हो जाएगा।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

93. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद के अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि कुछ टिप्पणियां दोहराई गई हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और जाँच परिणाम के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से उन पर ध्यान दिया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है:

- क. चीन जनवादी गणराज्य की गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के तर्क के संबंध में, वास्तविक क्षति, कारणात्मक संबंध, मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण क्षति, पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग के लिए एकाधिकार पैदा करेगा, मिहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड और एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रतिक्रिया को अस्वीकृत किए जाने और जनहित को इन जाँच परिणामों के संगत पैराग्राफ में प्राधिकारी द्वारा संबोधित किया गया है।
- ख. जहां तक आंकड़ों की वस्तुनिष्ठ जांच, ब्याज और मूल्यहास लागत के आंकड़ों को छिपाने और याचिका और प्रकटन विवरण में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- ग. जहां तक तिमाही-वार जांच का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि बिक्री कीमत में गिरावट मात्र का अर्थ तिमाही निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित किया है कि सामान्य मूल्य भी समय अवधि के साथ वास्तविक रूप से परिवर्तित हुआ है।
- घ. जहां तक भिवाड़ी संयंत्र को बंद करने और दाहेज संयंत्र के शुरू होने के संबंध में लागत में वृद्धि की बात है, यह नोट किया जाता है कि दाहेज संयंत्र की लागत और एनआईपी भिवाड़ी संयंत्र की तुलना में कम है। इसके अलावा, ये घरेलू उद्योग के केवल दो संयंत्र हैं, न कि दो अलग-अलग कानूनी कंपनियाँ।
- ङ. जहां तक क्षति विश्लेषण के लिए विचार किए गए वास्तविक आंकड़ों का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के वास्तविक सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- च. जहां तक देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में घरेलू उद्योग की क्षमता का संबंध है, प्राधिकारी ने रिकार्ड में जानकारी के आधार पर नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने *** मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 2016-17 के दौरान क्षमता में *** मीट्रिक टन, मार्च 2020 में *** मीट्रिक टन, और *** मीट्रिक टन (जनवरी 2021 तक) की वृद्धि की है। इसके अलावा घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास भारत में बहुत अधिक मात्रा में मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण, घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा और चीन के आयातों की तुलना में घरेलू बाजार में उसकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए जुलाई 2023 तक लगभग *** करोड़ के निवेश के साथ *** मीट्रिक टन फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजेंट और कुछ प्रमुख कच्चे माल की क्षमता में वृद्धि की घोषणा की है। किसी भी मामले में, संभावित मांग-आपूर्ति अंतर विचाराधीन उत्पाद के पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है, विशेषकर तब जबकि ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो।
- छ. पीसीएन वार एनआईपी के प्रकटीकरण के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन पर विचार नहीं किया है।
- ज. जहां तक सिनोकेम समूह द्वारा दायर किए गए उत्तरों को अस्वीकार करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि चूंकि हनीवेल ट्रेडिंग (शंघाई) कं लिमिटेड द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में सूचना पर प्राधिकारी ने निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए उत्पादक और निर्यातक द्वारा दायर किए गए उत्तरों पर

विचार नहीं किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक के प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते हुए अपनी सुसंगत पद्धति अपनाई है जहां प्रतिवादी उत्पादक द्वारा किए गए निर्यात के बड़े हिस्से का विवरण रिकार्ड में नहीं है।

- झ. जहां तक सामान्य मूल्य की गणना करते समय आबद्ध निविष्टि में उचित लाभ जोड़ने के तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपनी प्रथा के अनुसार आबद्ध निविष्टि में लाभ नहीं जोड़ा है। सभी आबद्ध निविष्टियों को उनकी उत्पादन लागत पर अंतरित कर दिया गया है और लाभ को उत्पादन की कुल लागत के प्रतिशत के रूप में जोड़ा गया है।
- ज. मिहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित संबद्ध वस्तु केवल चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32 के आयात हैं।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

94. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपाय लगाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन परिपाटियों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्य रूप में पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से किसी भी दशा में संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
95. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क लगाया जाना व्यापक जनहित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित है।
96. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनशीलता, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन बढ़ने अथवा विलंब होने की संभावना वाले कारकों से संबंधित सूचना मांगी।
97. चार आयातकों अर्थात् रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स मिहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड ने वर्तमान जांच का उत्तर दिया है। केवल मेसर्स रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। मेसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स मिहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने उत्तरों/अनुरोधों का अगोपनीय पाठ परिचालित नहीं किया। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में सभी हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है और मेसर्स एमपीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स मिहामा इंडिया प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर को खारिज कर दिया है। किसी भी उपयोगकर्ता, ओईएम या उपयोगकर्ता संघ ने वर्तमान जांच का विरोध नहीं किया है। न ही इन पक्षकारों ने यह दावा किया है कि प्रस्तावित एडीडी का बड़े पैमाने पर जनता पर या यहां तक कि उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि इन जांच परिणामों में पहले ही उल्लेख किया गया है, इनमें से किसी भी आयातक ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राधिकारी पुनः दोहराते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयातों को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए, यह उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा।

98. यहां तक कि यद्यपि प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए प्रारूप विहित किए हैं और विस्तार से बताया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संगत सूचना नहीं दी है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य सूचना के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को सिद्ध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता उद्योग पर सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है और अनुरोध किया है कि प्रभाव बहुत कम है।
99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई के बाद के अपने लिखित अनुरोधों के साक्ष्य प्रदान किए हैं कि पीयूसी का उत्पादन चीन में वैश्विक स्तर पर किया जाता है जिसकी क्षमता 2,84,000 एमटी है, यूएस की क्षमता 25,000 एमटी है, भारत की क्षमता *** एमटी है; दक्षिण कोरिया की क्षमता 9500 मीट्रिक टन और जापान की क्षमता 6000 मीट्रिक टन है। यह उत्पाद मुक्त श्रेणी के अंतर्गत है और इसलिए, विभिन्न देशों से स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से चीन से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होगा और इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने से न तो उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित होगी और न ही एकाधिकार पैदा होगा।
100. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी चीन जनवादी गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में विचाराधीन उत्पाद के आयात की जांच की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आयातों से उनके घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, उक्त आयातों पर बहुत अधिक मात्रा में शुल्क लगाया। अमेरिकी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए शुल्कों की राशि 161% - 221% के बीच है, जो यह दर्शाता है कि चीन अन्य देशों में पाटन के कितने अधिक स्तर को अपना रहा है।
101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद की खपत आवासीय एयर कंडीशनिंग में की जाती है और घरेलू उद्योग ने कहा है कि घरेलू एसी उत्पादन में वृद्धि का अनुमान है और भारत में अगले दशक में एचएफसी में मजबूत वृद्धि की संभावना है जिसका कारण है एचएफसी 32 और एचएफसी 410ए के साथ एचसीएफसी 22 के प्रतिस्थापन के साथ मिलकर एयर कंडीशनर (एसी) बाजार में भारी वृद्धि होना है। घरेलू उद्योग ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए क्षमता में 2016-17 के दौरान *** मीट्रिक टन, मार्च, 2020 तक *** मीट्रिक टन और *** मीट्रिक टन (जनवरी 2021 तक) की वृद्धि की है और जुलाई 2021 तक लगभग *** करोड़ के निवेश के साथ *** मीट्रिक टन फ्लोरोकार्बन रेफ्रिजेंट और कुछ प्रमुख कच्चे माल की क्षमता में वृद्धि की घोषणा की है।
102. इसके अलावा घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के पास भारत में बहुत अधिक मात्रा में मांग को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण, घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा और चीन के आयातों की तुलना में घरेलू बाजार में उसकी हिस्सेदारी बहुत कम हो गई थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जब अमेरिका और जापान में पर्याप्त क्षमताएं हैं, तब भी इन देशों से कोई आयात नहीं होता है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन ने इन देशों को भारतीय बाजार में बिक्री करने से रोक दिया है।
103. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि संबद्ध सामानों की कीमतों ने उपभोक्ताओं को कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए मात्रात्मक सूचना प्रस्तुत की है कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत कम है और इसका अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यह मानते हुए कि 1 टन की क्षमता वाले एक एयर कंडीशनर की कीमत 20,000 से 40,000 रु. है। एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले एचएफसी घटक आर-32 की मात्रा 1 किलो से कम होगी। मान लें कि 1 किलो एचएफसी घटक आर-32 की कीमत लगभग 200 रुपये है तो अंतिम उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता पर विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत कम है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि उत्पाद का उपयोग एक बार नहीं होता है और कई रिफिल होते हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि एसी में उत्पाद की पूरी लागत मात्र 200 रुपये, यहां तक कि रिफिल की लागत भी महत्वपूर्ण नहीं है।
104. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापन योग्य जानकारी के साथ प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित एडीडी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं किया है। इस प्रकार, भले ही यह मान लिया जाए

कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके विनिर्मित उत्पाद के मूल्य स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है, तब भी अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव अत्यधिक महत्वहीन होगा। इसके अलावा, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, खासकर यदि पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निवारण के लिए आवश्यक राशि तक सीमित है। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य पाटन प्रथाओं से प्राप्त अनुचित लाभ को दूर करना है; घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को रोकना है और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना है।

105. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि शुल्क लगाने की सिफारिश तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग अक्सर व्यापार संरक्षण का उपयोग करता रहा है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि वह 71 उत्पादों के उत्पादन में लगा हुआ है और वर्तमान में 4 उत्पाद में एडीडी द्वारा संरक्षित है। चीन से नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक और मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर पहले से लागू एडीडी अब लागू नहीं हैं।
106. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह भी नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है और प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाया जाना जनहित में होगा।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

107. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:
 - क. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।
 - ग. आवेदन में जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ समस्त संगत जानकारी दी गई थी और आवेदन में जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे।
 - घ. संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और मार्जिन काफी अधिक है।
 - ङ. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चीन से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग द्वारा महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि और इसके उत्पादन में वृद्धि के बावजूद काफी अधिक बनी हुई है। संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हो रहा है। 2018-19 तक बढ़ने के बाद क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है, जांच की अवधि में उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में प्रति इकाई लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी गिरावट आई है। देश में अत्यधिक मांग और जांच की अवधि में मांग-आपूर्ति के अंतर के बावजूद घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा है।
 - च. घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति, पाटित आयातों के कारण हुई है।
 - छ. एडीडी के प्रभाव को मापने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने और यह विस्तार से बताने के बावजूद कि एडीडी उन्हें प्रतिकूलतः कैसे प्रभावित करेगा किसी भी उपभोक्ता ने संभावित प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने से स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल और वास्तविक प्रभाव पड़ेगा, जबकि शुल्क लगाने से उपभोक्ता या डाउनस्ट्रीम उद्योग या व्यापक पैमाने पर जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और की गई जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह सुविचारित मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा प्रस्तावित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में पाटन की जांच शुरू करने और जांच करने पर तथा पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने तथा लगाए जाने के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करने लेने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
109. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाम की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुँच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर के अनुसार आकलन योग्य मूल्य होगा।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष	विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	290339	हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर - 32	चीन जन. गण.	चीन जन गण सहित कोई देश	शानडोंग डोंगयी कैमिकल कं. लि.	1,171.78	एमटी	अम.डा.
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन गण सहित कोई देश	झेजियांग कुझाउ जूक्सिन फ्लोरिन कैमिकल कं. लि.	1,394.96	एमटी	अम.डा.
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन गण सहित कोई देश	जिआंगसु सनमेई कैमिकल इंड. कं. लि. और फुजियान किंगलू डांगयिन कैमिकल इंड. कं. लि.;	1,344.60	एमटी	अम.डा.
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन गण सहित कोई देश	जिबो फियुआन कैमिकल कं. लि.	1,255.05	एमटी	अम.डा.
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन गण सहित कोई देश	क्र.सं 1 से 4 से इतर कोई	1,519.70	एमटी	अम.डा.
6	-वही-	-वही-	चीन जन गण से इतर कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	1,519.70	एमटी	अम.डा.

ड. आगे की प्रक्रिया

110. इस सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd September, 2021

Case No. AD (OI)-28/2020

Subject : Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32, originating in or exported from China PR -reg.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/33/2020-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application (also referred to as the “petition”) from M/s SRF Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant” or the “Domestic Industry”) requesting initiation of anti-dumping investigation under the Act and the Rules on imports of “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”). The Applicant, namely, M/s SRF Limited has provided the prescribed information in the application.
2. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/33/2020-DGTR dated 28th September, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 28th September, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 28th September, 2020, to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it

along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties from time to time up to 20th December, 2020 to file their Questionnaire response/submissions.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s Zhejiang Yonghe Refrigerants Co. Ltd.
 - ii. M/s The Chemours 3F Fluorochemicals (Changshu) Co. Ltd.
 - iii. M/s Ninhua Group Co. Ltd.
 - iv. M/s Sinochem Environmental Protection Chemical (Taicang) Co. Ltd.
 - v. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind Co. Ltd.
 - vi. M/s Zibo Feiyuan Chemicals Co. Ltd.
 - vii. M/s Sinochem Environmental Protection Chemical Co. Ltd.
 - viii. M/s Jinhua Yonghe Fluorochemical Co. Ltd.
 - ix. M/s Hangzhou Juming Imp/Exp Co. Ltd.
 - x. M/s Dongyang Weihua Refrigerants Co. Ltd.
 - xi. M/s Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co. Ltd.
 - xii. M/s Lu Xi Chemical (Hong Kong) Co. Limited.
 - xiii. M/s The Chemours Chemical (Shanghai) Co. Ltd.
 - xiv. M/s Daikin Arkema Refrigerants Asia Limited.
 - xv. M/s Zhejiang Lantian Environmental Protection Fluoro Material Co. Ltd.
 - xvi. M/s Fluo Shanghai International Trade Co. Ltd.
 - xvii. M/s Beijing Straget Chemicals Co. Ltd.
 - xviii. M/s Zibo Feiyuan Chemical Co. Ltd.
 - xix. M/s Zhejiang Fotech International Co.
 - xx. M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
 - xxi. M/s Zhejiang Orient Multitex I/E Co. Ltd.
 - xxii. M/s Ace Prosper Corporation.
 - xxiii. M/s Dyaninc Limited.
 - xxiv. M/s Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd.
 - xxv. M/s Jiangxi Lee & Man Chemical Limited.
 - xxvi. M/s Sc Ningbo International Ltd.
 - xxvii. M/s Shandong Huaan New Material Co. Ltd.
 - xxviii. M/s Liancheng Ruijin (Hong Kong) Co. Limited.
 - xxix. M/s Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co. Ltd.
- h. In response to the above notification, the following exporters/ producers and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporter's questionnaire responses and/or legal submissions:
- i. M/s Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co. Ltd. (Producer)
 - ii. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Exporter)
 - iii. M/s Zibo Feivuan Chemical Co. Ltd. (Producer and exporter)

- iv. M/s Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer and exporter)
- v. M/s Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd. (Exporter)
- vi. M/s Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co. Ltd. (Producer)
- vii. M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. (Producer)
- viii. M/s Taixing Meilan New Materials Co. Ltd. (Producer)
- ix. Taizhou Qingsong Refrigerant New Material Co. Ltd. (Producer and exporter)
- x. M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd. (Exporter)
- xi. M/s Taixing Meilan Zhinglan New Materials Co. Ltd. (Trader)
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. M/s Gorakhram Haribux.
 - ii. M/s Kiro Refrigerants Private Limited.
 - iii. M/s Stallion Enterprises.
 - iv. M/s Mangali Petrochem Ltd.
 - v. M/s Ajay Air Products (P) Ltd.
 - vi. M/s Gujarat Fluoro Chemicals Ltd.
 - vii. M/s Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd.
 - viii. M/s Coolmate Refrigerants Pvt. Ltd.
 - ix. M/s Chillaire Solutions.
 - x. M/s Mihama India Pvt. Ltd.
 - xi. M/s Value Refrigerants Private Limited.
 - xii. M/s MPCL Industries Limited.
 - xiii. M/s Navin Fluorine International Limited.
 - xiv. M/s Vijay Petrochem Private Limited.
 - xv. M/s Shravan Engineering Enterprises P. Ltd.
 - xvi. M/s Sikelan Chemicals India Pvt. Ltd.
 - xvii. M/s Refex Industries Limited.
 - xviii. M/s Mexfluor India Private Limited.
 - xix. M/s T.T. International Co. Ltd.
 - xx. M/s Weitron International Refrigeration Equipment (Kunshan) Co. Ltd.
 - xxi. M/s Aone 9 Star Future Pvt. Ltd.
 - xxii. M/s Unique General Trader.
 - xxiii. M/s Karthik Traders.
 - xxiv. M/s Hindustan Refrigeration Stores.
 - xxv. M/s Cool Chem (Opc) Private Limited.
 - xxvi. M/s Koolane Refrigerants.
- j. In response, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions:
 - i. M/s Refex Industries Ltd. (Importer)
 - ii. M/s MPCL Industries Ltd. (Importer)
 - iii. M/s Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. (Importer)

iv. M/s Mihama India Pvt. Ltd. (Importer)

- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to restrictions on physical movements owing to ongoing global Covid-19 pandemic.
- l. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2019 to 31st March, 2020 (12 months). The injury examination period is the period 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019 and the period of investigation.
- m. The Authority obtained transaction-wise import data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the subject goods for the injury period, including the period of investigation, and analysed the data after due examination of the transactions.
- n. Verification of the data provided by the domestic industry and the responding exporters was concluded to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
- o. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits for the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held through video conferencing on 30th June, 2021. The parties, which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.
- q. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered in this final findings.
- r. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties which forms the basis of this final findings, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant.
- s. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- t. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 26th August, 2021, and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these Final Findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiterations of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.
- u. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the

investigation, the Authority has considered such party as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.

- v. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.65.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

“3. The product under consideration in the present application is “Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane”. R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH₂F₂ and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. The HFC Component R-32 is mainly used in residential air conditioning systems.

4. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under customs sub-heading no. 290339. The customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

C.1. Submissions of the domestic industry

- 5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and the like article that are considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH₂F₂ and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. HFC Component R-32 is used in residential air conditioning systems.
 - b. This product is classified under Customs Tariff heading no. 290339.
 - c. The Applicant has produced like article to the imported products.
 - d. The domestic industry has no objection to separate margins being calculated for packed and unpacked forms of the PUC.

C.2. Submissions of other interested parties

- 6. The following submissions have been made by the exporters/producers/other interested parties regarding the product under consideration and like article:
 - a. Packed and unpacked forms of the PUC have a cost and price difference of 20-30%. No such differentiation is made for goods while claiming dumping and injury in the petition. The Authority should compare them separately and separate margins should be determined

C.3 Examination by the Authority

- 7. The product under consideration in the present investigation is “Hydrofluorocarbon Component R-32” or “Difluoromethane”.
- 8. Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32 or Difluoromethane has the chemical formula CH₂F₂ and is registered as CAS No. 75-10-5. It is also known as HFC-32, FC-32, Freon-32, Methylene difluoride, Methylene fluoride, Carbon fluoride hydride, halocarbon R32, fluorocarbon R32, and UN 3252. HFC Component R-32 is used in residential air conditioning systems.
- 9. The product is classified under Customs Tariff heading no. 290339. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.
- 10. As regards the argument of separate dumping margin of packed and unpacked product under consideration, it is clarified that the Authority has determined separate margins for packed and unpacked forms. The dumping and injury margins have been determined as the weighted average of the dumping margins for the packed and unpacked forms.
- 11. It is seen from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product

produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

12. The domestic industry (DI) has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - a. The Applicant, namely M/s SRF Limited, constitutes 100% of the domestic production for the subject goods in India.
 - b. The Applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject country.
 - c. The Applicant is not related to any exporters in the subject country or importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions of other interested parties

13. No submissions have been made by the exporters/producers/other interested parties regarding the scope and standing of the domestic industry.

D.3.Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
15. The Application has been filed by M/s SRF Limited. The Applicant accounts for 100% of the Indian production. The Applicant has certified that neither they have imported the PUC from the subject country in the period of investigation nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject country or any importer of the PUC in India.
16. The Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. The Non-Confidential Version (NCV) of the petition and Annexure A filed are as per Rule 7 of the AD Rules, Trade Notices 1/2013 and 10/2018.
 - b. Mihama India, Stallion India and MPCL have not circulated the NCV of their submissions to the DI in violation of relevant legal provisions, trade notices issued by the Authority and global best practices. They have also not participated in the hearing. These parties should not be considered interested parties. CESTAT order in HR Johnson v. Designated Authority is relied upon.
 - c. Several responding parties have claimed their related party information confidential in violation of Trade Notice 10/2018.
 - d. All interested parties have resorted to excessive confidentiality on multiple grounds. This impairs the right of defense of the domestic industry and violates principles of natural justice.
 - e. NIP is business sensitive information, not amenable to summarization.

- f. DGCIS data is third party data which the DI is not authorized to disclose. The same may be obtained following Trade Notice 7/2018. Final Finding in AD investigation on 'PET Resin' from China is relied upon. There is no obligation on the DI to provide both sorted and unsorted data to all interested parties.

E.2. Submissions of other interested parties

18. The other interested parties have made the following submissions with regard to confidentiality:
 - a. NIP has not been provided as per prescribed deviation of +/- 10%. The confidentiality claim provides no reasonable estimate of NIP claimed.
 - b. The Authority may disregard information on which confidentiality claim is not to the satisfaction of the Authority and the petitioner is unwilling to make information public.
 - c. The non-confidential version is not a replica of the confidential version and, therefore, the investigation should be terminated. During the oral hearing, the domestic industry mentioned that replica of Confidential Version (CV) petition in NCV has no meaning and made its submissions as if it has got the right to provide the information as it likes and in no case it will provide the replica of the confidential version.
 - d. The non-confidential version of the petition violates requirements of the Rules, relevant trade notices and the right of defence of the interested parties by not furnishing any information in response to Annexure A (Injury Statement) and Annexure 4 (Costing Information).
 - e. The petitioner does not claim that the production process is patented and the raw material used is proprietary to them. Even a broad description of the manufacturing process has been kept confidential on vague grounds.
 - f. The domestic industry has kept lots of information confidential without any legitimate reasons and in violation of rules and procedure of the Authority. Item-wise details of normal value, evidence of adjustments for export price, profit/loss and return on capital employed in percentage terms, price underselling and injury margin, share in total production, details of wages have been kept confidential.
 - g. Formats A to L are left completely blank without even disclosing basic information.
 - h. On a number of other parameters also like R&D expenses, funds raised, export price/unit, PBIT per unit, purchase of PUC, and NIP calculation, the Applicant has violated the trade notice without good cause for claiming excessive confidentiality. The information for these parameters should be disregarded.
 - i. The petitioner has also not provided transaction-wise import data. CESTAT decision in Exotic Décor is relied upon.
 - j. The DI has claimed excessive confidentiality on related party transactions.
 - k. Responding to the submission of the domestic industry, the interested parties have contended the following:
 - i. The DI is wrong in arguing that excessive confidentiality has been claimed by the exporters.
 - ii. Zibo Feuyuan has provided cost, price, and PBIT of export to India in confidential version.
 - iii. DI's objections to confidentiality are without a proper review of questionnaire response. While exporters have claimed manufacturing process is claimed confidential, the same has been claimed by the DI too. The confidentiality claimed is permissible under the Rules by providing reasons which are not disputed by the DI.
 - iv. Shandong has provided information on related parties in the confidential version as per the Rules.

E.3. Examination by the Authority

19. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”

20. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of a significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significant adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.
21. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicant and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).
22. As regards submission of importer's questionnaire response by Mihama India Pvt. Ltd., Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd., and MPCL Industries Limited, it is seen that these companies have not provided a meaningful summary of the confidential submissions in the form of non-confidential version. The Authority therefore rejects the questionnaire response filed by these companies.
23. With regards to DGCI&S data, the Authority notes that the data has been shared with interested parties relating to volume & value of imports from exporting countries into India. It is also noted that any interested party can obtain data independently from the DGCI&S and lodge its own counter claim based on the data so received. The Authority holds that procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March, 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Due to Covid-19, a scanned copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per the prescribed format. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests
24. The Authority notes that both set of interested parties have claimed similar information as confidential and have yet pointed out at confidentiality claimed by other interested parties on similar information. The Authority notes that the information claimed confidential by these interested parties on these accounts are normally allowed to be filed on confidential basis. Since the Authority has allowed confidentiality on such information in the past, the same has been allowed in the present case as well.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

25. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. The questionnaire responses filed by the Chinese producers are incomplete in so far as these do not include questionnaire response of the affiliated parties. All related parties of the responding companies had responded in the investigation conducted by the US. However, some of these parties have not responded in the instant investigation. Further, as per the instructions contained in the questionnaire, all related entities engaged in the PUC and unrelated exporters exporting the PUC should file questionnaire responses. If such related parties have failed to cooperate, the responding party should also be held non-cooperative.
- b. From publicly available information, certain related parties of Sinochem Lantian, Zhejiang Sanmei, and Shandong Dongyue engaged in the PUC are non-cooperative, as these parties have not filed questionnaire response.
- c. The imposition of the ADD will not be against public interest. The objective of ADD is to redress unfair price discrimination which is injurious to the industry in India. It establishes a level playing field, removes trade distortion and allows fair competition. It addresses the decline in the DI's performance and does not adversely impact eventual end customers. It will not restrict imports or affect availability of the product. Indigenous production guarantees reliability of supply.
- d. Participation by consumers and importers is quite minimal. No users or user Association in India has opposed the imposition of the ADD. This shows they do not consider any significant adverse impact as a result of the investigation. Since the cost of the PUC on the final product is very minimal, there is no effect on the end-users.
- e. Considering number of products produced by SRF, the company has not frequently approached the Authority seeking imposition of ADD. This shows the Applicant is responsible and a fair player.
- f. The commencement of production of the PUC by the Applicant is in line with the PM's Atma Nirbhar Bharat initiative. It is in the interest of the public at large to have a strong competitive domestic production of the subject goods. If injury to the DI continues, the consumers will be completely at the mercy of foreign producers.
- g. DI filed data for 11 months since the DGCIS data for March 2020 was not available at the time of filing.

F.2. Submissions of other interested parties

26. The other interested parties have made the following miscellaneous submissions:

- a. The domestic industry has provided import data for only 11 months and not the entire period of investigation. Since DGCIS data and the sorted import data is not being provided to the interested parties, it is very easy for the domestic industry to manipulate import data. Domestic industry has hidden the information. The Authority should make it mandatory for the domestic industry to provide raw import data, sorted import data and excluded import data.
- b. Incorrect calculation of import price by the use of only 11 months data has led to incorrect calculation of dumping margin. Hence, petition is unreliable and information provided by the producers/exporters should be considered. The petitioners should be directed to revise the petition to include data till March 2020.
- c. AD and SSR investigations on R134a and AD investigation on imports of HFC Blends show that the petitioner has been seeking undue protection from the Authority for 12 years to attack the producers and exporters in China PR, maximise profits and gain monopolistic advantage.
- d. The DI uses trade remedy as a strategic decision to offset their immense increase in costs during the POI. The same should be examined.
- e. Since SRF is the sole producer, the whole market will be served only by them regardless of the quality and will derive market power from barriers to entry of potential competitors, thereby harming competitive environment and healthy development of industry of India. There are 100% chances of price extortion and price discrimination.
- f. Annual Report 2019-20 shows that 13% of customer complaints were in the fluorochemical business, which includes HFC R-32 and demonstrates that the product is of poor quality

thereby preventing them from producing quality grades and speciality grades of product under consideration.

- g. Imposition of anti-dumping duty will affect end-users and downstream industry who are dependent on internationally competitive raw material to manufacture value-added products that can compete with other countries. It would cause tremendous loss of livelihood, reduction in exports by MSMEs, market asymmetry between manufacturers and limited availability of inferior quality of goods. Petitioner's capacity to produce PUC is limited. Users in India prefer imports to cater to high demand requirement.
- h. Imposition of ADD will also limit choices in ACs for consumers in India as Government has already prohibited import of ACs with refrigerants in India. ADD will strengthen the monopoly of the petitioner and lead to abuse of dominance. Petitioner is seeking ADD to protect its investment from legitimate competition and strengthen their monopoly.
- i. PUC is crucial for measures against climate change. Many downstream manufacturers in India are moving to the PUC as constituent gas. Hence, imposition of ADD will affect its affordable availability forcing use of gases with higher Global Warming Potential (GWP) like R-410A. The PUC has several inherent advantages over R-410A. Hence, the affordability of the PUC is also important in public interest.
- j. Public interest should be considered before imposition of duty, if any. Imposition of ADD will create loss of livelihood in the downstream industry and small end users, wide gap in demand and supply, reduction in export of finished goods in MSME industries, and market asymmetry between manufacturers. Public interest is in favour of non-imposition.
- k. The subject goods cannot be substituted. Imposition of ADD will affect the commercial viability for imports of this group of refrigerants. Since most ACs in India have shifted to the PUC and can't be later substituted, the imposition of ADD will impact the users.
- l. PUC is the most commercially viable, environment friendly, and practically convenient refrigerant gas.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority considered the submissions of the opposing parties and the domestic industry as follows:
- a. The Authority has examined the information on related parties filed by the cooperating producers/exporters and has ensured that all related parties engaged in the subject goods have filed required information as mandated by the Authority.
 - b. As regards the argument of impact of the ADD on the user industry, it is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted information showing that the impact of the proposed anti-dumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry submits that the cost of product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. For example, assuming that an air conditioner of a capacity of 1 Ton costs around Rs. 40,000. The amount of HFC Component R-32 used in the air conditioner would be less than 1 kg. Assuming that 1 kg of HFC Component R-32 costs around Rs. 200, the cost of the product under consideration on the end-consumer of the final product is very meagre.
 - c. It is, thus, noted that while the interested parties have not established impact of proposed ADD on the user industry with verifiable information, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

- d. As regards the use of only 11 months data by the domestic industry in filing their petition, the Authority has considered the import data for the entire POI in their assessment of export price, resultantly the dumping margin and injury parameters in the present determination.
- e. As regards excessive protection to the domestic industry, the Authority notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. Further, there is no bar on the number of times a duty can be imposed or extended on a given product. It is, however, noted that the domestic industry has reported that it is engaged in production of 71 products and is at present protected by ADD in 4 products. Further, the ADD earlier in force on imports of nylon tyre cord fabric and methylene chloride from China is no longer in force.
- f. As regards the argument that anti-dumping duty will create monopoly for domestic industry, the Authority notes that the PUC is produced globally in China, US, India and Japan. The product is under free category and, therefore, can be freely imported from various countries. Imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from China in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. Moreover, there is a separate entity to look into the allegations of monopoly and anti-competitive measures.

G. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETERS

NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the domestic industry

28. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - a. The Authority shall follow Para 1-6 of Annexure I for determination of the normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined.
 - b. Since the Chinese producers are not entitled to market economy treatment, Para 7 of Annexure I may be followed to determine the normal value.
 - c. The Authority considered China as NME in the initiation stage. Since none of the producers have demonstrated nor claimed market economy treatment, the normal value should not be calculated on the basis of domestic selling price or costs of the exporters. It should be based on Para 7 of Annexure I of the AD Rules. The same basis as in initiation notification should be followed.
 - d. The China is treated as an NME as per Article 15 of the Accession Protocol. Only Article 15(a)(ii) expired after 11th December, 2016. Article 15(a)(i) continues to remain in force. Hence, the domestic prices or costs of China is to be taken only if producers can show existence of market economy conditions. In the present case, they have failed to do so. The observations of the Appellate Body in EU-Fasteners are merely obiter dicta. The Authority has considered China as NME in all recent investigations. Final Finding in SSR investigation on imports of 'Electric Insulators' from China is relied on. The same view has been taken in other Findings as well.
 - e. The normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
 - f. The Applicant has claimed the determination of normal value for China on the basis of price payable in India duly adjusted. For the determination of Normal Value in the subject country, the Applicant has taken the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general, and administrative expenses and reasonable profit margin.

- g. The Applicant has taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses, commission, bank charges and VAT to determine the export price.
- h. The dumping margin is not only significant but also substantial for the subject country.
- i. Adverse inference should be drawn on non-participation. On non-cooperation, facts available should be applied.
- j. For producers with exports through unrelated non-cooperative exporters, the Authority is requested to determine share of exports through such exporters. In case the share is not significant, the responding producer should be held non-cooperative. Para 16.26 of the Manual of Operating Practices is relied on. Even if it is below the threshold, export price should be calculated for all sales and adverse facts should be applied.
- k. The adjustments claimed by the DI are consistent with practice of the Authority. The DI has no objection to export price and dumping margin being determined based on information filed by the exporters subject to its accuracy and adequacy. However, since none has claimed NME, normal value shall be based on information provided by the domestic industry.

G.2. Submissions of other interested parties

29. The other interested parties have made the following submissions regarding the normal value, export price and dumping margin:
- a. The export price and dumping margin should be determined as per actual data provided by the respondents.
 - b. According to the protocol on China's accession to the WTO, the surrogate country practice in anti-dumping actions should be lacking in multilateral legal basis since 11th December, 2016. The surrogate country methodology should not be used in calculating the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy country. India has no basis for calculating normal value using the non-market economy methodology. Ref: EU – Fasteners wherein it was stated that interpretation of relationship between 15(a) and 15(b) of the protocol justifies China automatically obtaining the market economy status once Article 15 of the protocol expires.
 - c. China must be treated in the same way as any other WTO member for anti-dumping investigations, a view that was shared by US and EU until recently. The Authority is requested to grant market economy status to China, conduct normal value calculation as per Art. 2 of the ADA and apply the data on costs and prices in this response for the determination of the normal value rather than applying analogue country data in this investigation.
 - d. The domestic industry has arbitrarily constructed normal value without following due procedure as per para 7 of Annexure I of the AD Rules. Ref: SC decision in Shentang Matsushita – proceedings cannot continue in view of absence to follow mandatory procedure. The normal value has been inflated due to non-utilization of optimum capacity by the domestic industry.
 - e. Though exports were also made by a Chinese producer through an unrelated exporter, the share of exports through co-operating exporter is more than the threshold for individual margin determination. Non-cooperation by an unrelated party should not be held against the cooperating parties.
 - f. Petitioner's claim on increase in basic raw material price (fluorspar) needs scrutiny. Exaggerated numbers are apparently used to inflate dumping margin and has no basis.
 - g. Applicant has not provided evidence for deductions made on ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission, bank charges, and VAT paid by Chinese exporters for calculation of export price. Deduction on marine insurance is grossly inflated and liable to be rejected. The same should be verified from exporter responses.
 - h. A separate comparison of packed and unpacked forms should be undertaken.
 - i. The claims of dumping margin by the DI is a result of constructed normal value to inflate it.

G.3. Examination by the Authority

30. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*
 - (b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

- i. M/s Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co. Ltd.
- ii. M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
- iii. M/s Zibo Feivuan Chemical Co. Ltd.
- iv. M/s Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd.
- v. M/s Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co. Ltd.
- vi. M/s Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co. Ltd.
- vii. M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.
- viii. M/s Taixing Meilan New Materials Co. Ltd.
- ix. Taizhou Qingsong Refrigerant New Material Co. Ltd.
- x. M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co. Ltd.
- xi. M/s Taixing Meilan Zhinglan New Materials Co. Ltd.

Market Economy Status for Chinese Producers

32. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that

product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

33. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producers/ exporters from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.
34. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject country have been determined as below.

G.4 Determination of normal value

35. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

36. The Authority notes that the prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the Applicant or an interested party, nor is available with the Authority from any public source. The Authority notes that the Authority is required to select an appropriate country on the basis of information and evidence brought on record by the interested

parties. It is also noted that the interested parties have not provided any verifiable information which could have been adopted by the Authority. Thus, the Authority is of the opinion that the only option available is to determine the normal value considering price actually paid or payable in India for the like article which has been determined considering optimised cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The normal value so determined is given in the dumping margin table below.

G.5. Determination of export price for China PR

Shandong Dongyue Chemical Co. Ltd. (Producer/Exporter)

37. M/s Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has filed a questionnaire response in the form and manner prescribed and furnished the requisite information to determine the net export price. During the POI, M/s Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has directly exported *** MT of PUC for *** US\$ to India in unpacked form. M/s Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation and port and other related expenses, which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for M/s Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd. calculated by the Authority is given in the dumping margin table below.

Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. (Producer) and Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd. (Exporter)

38. M/s Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. ("Juxin") and Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd. ("Quhua") are limited companies by shares under the Company Law of China PR. Juxin is the producer of the subject goods in China PR and has exported subject goods to unrelated Indian customers through Quhua. Both the companies have provided all the relevant information in requisite questionnaire formats. It is noted that during the POI, Juxin has exported *** MT of subject goods for *** US\$ through Quhua to unrelated customers in India in unpacked form. Juxin and Quhua have claimed adjustments on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and credit cost which have been allowed by the Authority. The ex-factory export price calculated by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. (Producer), Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd., (Producer) and Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., (Related Exporter)

39. Exporter Questionnaire Responses have been filed by M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. and M/s Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd who are two related producers of the subject goods in China. Subject goods produced by these two related producers have been exported to India through a related exporter, namely, M/s Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. Responses of all the three companies are available in the prescribed format and, hence, the chain of exports to India is noted as complete. It is noted from the response that during the POI, Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd has exported *** MT of the subject goods to India, out of which *** MT have been produced by M/s Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd and balance *** MT were produced by Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. It is claimed that all these materials are exported in unpacked form only. Exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, inland transportation, marine insurance which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for the group calculated by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd. (Producer/Exporter)

40. The Authority notes that M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd., China, has responded in this investigation and has provided the requisite information to determine the net export price. During the POI, the company has directly exported ***MT for US\$ *** to India in unpacked form. The exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, port and handling expenses, credit cost and bank charges which have been allowed by the Authority. Accordingly, the net export price at ex-factory level for the company calculated by the Authority is given in the Dumping Margin Table below.

M/s Taixing Meilan New Materials Co., Ltd. and Taizhou Qingsong Refrigerant New Materials Co., Ltd. (Producer); M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd. (Exporter/Trader) and M/s Taixing Meilan Zhonglan New Materials Co., Ltd. (Domestic Seller), China PR

41. During the POI, M/s Taixing Meilan New Materials Co., Ltd. and Taizhou Qingsong Refrigerant New Materials Co., Ltd. (Producer) has indirectly exported *** MT of PUC of value *** US\$ to India through Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd. in unpacked form. Further, it is noted that M/s Sinochem Lantian Fluoro Materials Co., Ltd., a related company of M/s Taixing Meilan New Materials Co., Ltd., has directly exported *** MT of the PUC for *** US\$ to India. However, Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd. has not filed its exporter's questionnaire response with the Authority. Since, the information in respect of significant exports is not available, the Authority does not consider the responses filed by the producer and exporter for determination of the export price. Therefore, the producer is treated as non-cooperative.

Non-cooperative Exporters from China PR

42. Export price in respect of other (non-cooperative) exporters from China PR calculated as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producers and exporters.

G.6 Determination of Dumping Margin

43. It is noted that a number of cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been the consistent practice of the Authority to consider related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and, thus, to establish one single dumping margin for them. Therefore, all related producers and exporters have been treated as one single entity and attributed one single dumping margin, which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margin of these cooperating related producers and exporters.
44. Considering the normal value and export price for subject goods calculated as above, the dumping margins for the subject goods from subject country is as follows:

Dumping Margin Table

Sl. No.	Producer	CNV (US\$/MT)	NEP (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
2.	Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. exported through Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd.	***	***	***	***	70-80
3	Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. and Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd; exported through Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	***	***	***	***	70-80
4.	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
5.	All Others	***	***	***	***	90-100

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of the domestic industry

45. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- a. The injury information provided by the DI pertains only to the subject goods. The data is normated since capacity utilization was very low in the base year due to new plant. The DI provided data considering maximum capacity utilization/ projected capacity utilization. Still most parameters show deterioration.
 - b. Section 11(2) of the AD Rules require the Authority to determine injury to DI which under Rule 2(b) means domestic producers “as a whole”. A plant wise assessment is not permitted.
 - c. Imports from the subject country constitute 100% of the imports of the subject goods into India. This shows the inability of producers from other countries to match the prices offered by the Chinese producers. This would not have been possible without high capacities. The subject imports have increased significantly throughout the injury period in absolute as well as relative terms.
 - d. The import price of the subject imports has declined significantly during the POI. The subject imports are undercutting, suppressing and depressing the prices of the domestic industry. The landed price is below cost of the DI throughout the injury period except 2017-18. Price undercutting and positive injury margin are “one of the factors” to determine whether dumped imports are causing injury to the DI.
 - e. There is no requirement in law to provide price underselling or injury margin information at petition stage.
 - f. The purpose of four-year injury period is for the assessment for the entire period. Since DI commenced production shortly before the injury period, it is natural that performance is weak in the base year.
 - g. The capacity expansion in the POI is a result of the DI’s long-term commitment in keeping up with the increasing domestic demand and making India Atmanirbhar with respect to the subject goods. Major sales have taken place from the old plant. The increase in interest cost, which is insignificant compared to total costs, has no impact on injury data.
 - h. Demand higher than domestic capacity justifies imports but not dumping. Considering the volume of imports, DI is forced to follow import prices while offering its prices.
 - i. The DI suffered adverse volume effect and severe price injury. The CESTAT decision in *DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority and Final Finding in AD investigation on ‘Natural Mica based Pigments excluding cosmetic grade’ from China* are relied on.
 - j. The capacity utilization of the domestic industry declined significantly in the POI. The domestic industry has been unable to increase its market share after 2018-19, which would have been 67% in the absence of the dumped subject imports. The market share of the DI is very low compared to that of the subject imports. The inventories with the domestic industry have increased significantly in the POI. The ratio between domestic sales and inventory deteriorated significantly in the POI showing the impact of dumping.
 - k. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. A significant decline is seen in the POI in terms of PBIT, cash profits, and ROCE. The domestic industry is suffering losses in the POI. The growth of the domestic industry is negative in almost all injury parameters. The domestic industry’s ability to raise capital has also weakened.
 - l. China has significant surplus capacity which is sufficient to meet demand in all prominent markets. The producers of the subject goods in China hence rely on export markets substantially. However, the US market is closed to them due to imposition of ADD. The imposition of ADD on the subject goods from China by the US shows the Chinese producers are not only dumping in India but also in other countries. The quantum of duties imposed shows the significant dumping by Chinese producers.

- m. The analysis of the questionnaire responses filed by the responding producers/ exporters shows that they have enhanced their capacities despite surplus capacities available. The landed price of subject imports declined despite increase in prices of fluorspar. This shows cost and prices of subject imports are not fixed based on raw material prices. The respondents have relied on East China Fluorspar prices without providing source of information and it does not reflect prices in China. It also shows the NME status of China. The respondents have not disputed the fact that despite increase in fluorspar prices, landed price has declined.
- n. Price undercutting being caused by the dumped subject imports has led to the significant suppressing and depressing effect on the prices in the domestic market. Consequently, profitability of the domestic industry declined significantly to such an extent that the domestic industry was unable to cover its cost of production. Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits are directly a result of dumped imports. The fact that productivity has increased shows that injury is not due to productivity of the DI.
- o. The Annual Report of the domestic industry refers to the business segment that includes the PUC and other products. The Annual Report refers to the company as a whole and not just the domestic performance and that of the PUC. The shutdown of the Dahej plant for 8 days cannot be a reason for overall deterioration of the DI. Other public statements also do not alter the cause of injury to the DI. The respondents have not provided any evidence to show the product by the DI is inferior. Dahej plant commenced production in August, 2019 and hence, the argument of effect of flood is factually incorrect.

H.2. Submissions of other interested parties

46. The other interested parties have made the following submissions regarding injury and causal link:

- a. No methodology has been provided by the DI for selection of the narrowest group/ range of products for injury analysis. The Authority should conduct detailed verification of cost allocation by the DI between PUC and other products.
- b. There is inconsistency in the information on production of the DI as per Annexure 2.2 and Proforma IV-A. The petitioner should be directed to clarify why data in Format H is normated.
- c. DI has performed extremely well in the POI compared to the base year and has not suffered any injury. Claims by DI on dumping and fall in landed price has no meaning when seen in the context of import of the subject goods in India and performance of the DI amid alleged dumping. Decline in landed price is not actionable. The import trend for China does not reflect pressure of excess capacity. The market share of the imports declined while that of DI increased significantly. Thus, DI claimed market share even when price undercutting claimed is very significant.
- d. Increase in subject imports should be seen in light of increase in demand and DI's commencement of production only in 2016-17. The increase in domestic sales of DI is much more than increase in import volumes leading to capturing of market share. Subject imports increased only commensurate with demand increase. The decline in landed price in the POI compared to the previous year was due to developments in the HFC market in 2020, i.e., increased global demand. Import price has to be viewed in this background.
- e. DI's capacity has not increased corresponding to the increase in demand. If DI did not have sufficient capacity to meet domestic demand from 2016-17 to 2018-19, the downstream industry would have no option but to import the subject goods and the subject imports would not have displaced domestic sales. The petition does not explain how DI increased its market share and profitability despite significant price undercutting.
- f. PBIT, cash profits, and ROCE is seen to increase significantly in the POI. Fall in profitability in POI compared to previous year has no merit as there is a significant rise compared to base year. The abnormal profits in the base year have only increased in the POI.
- g. Capacity utilization declined only in the POI when capacities were added. It is unreasonable to expect ROCE to increase in the same year in which capacity additions were undertaken. Productivity increased throughout the injury period and period of investigation. Average capital employed and return on capital employed has increased phenomenally in the period of

investigation. There is no impact on number of employees, wages, growth and ability to raise capital investment. Mere existence of positive price undercutting, injury margin per subject exporter does not imply that domestic industry has suffered injury. By not claiming price underselling, the petitioner has admitted there is no price underselling. Hence, as per lesser duty rule and injury margin being negative, the investigation should be terminated.

- h. Increase in capacity by the domestic industry has resulted in increase in interest cost, depreciation costs, wages and other overheads, thereby causing injury. The failure of causal link through abnormally high depreciation and finance charges leading to losses was found in safeguard investigation on Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series. Same facts are seen in the present case. Separate plant wise assessment of cost of production and injury parameters is necessary for objective assessment.
- i. Increase in inventories is due to increase in production quantity, installed capacity and capacity utilization. CESTAT order in *Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority* is relied upon where the relation between increase in inventories and increase in sales was discussed. In the present case, inventories increased with sales volume. Inventories must be seen in relation to production quantity and not in absolute quantity. In the present case, there is no relative increase.
- j. The PBIT of Chemical Segment of SRF Limited shows that the petitioner has been continuously making profits since 2016 which was highest in March, 2020. Since no separate information is provided for Fluorochemicals, it is assumed that the Chemical Segment includes both Fluorochemicals and Speciality chemicals. The Annual Report 2019-20 mentions a temporary shutdown in the Dahej site due to COVID -19 which the petitioner failed to mention in the petition. Injury to the domestic industry is due to the prolonged and severe slowdown in the auto and white goods sector as mentioned in the Annual Report. Petitioner's capacity utilization has increased despite increase in subject imports. The trend indicates petitioner increasing economies of scale. As per earnings call by the petitioner with its investors, their capacity utilization is 70-75% in the POI which is optimum for the industry.
- k. There is also a lack of correlation between import price/ price undercutting and profitability. The operations of the Dahej plant were affected and costs increased in Aug, 2019 due to floods in Dahej. Petitioner's capacity to produce PUC is limited. Technology available with the DI is obsolete. This has contributed to lower economies of scale and higher cost of production.
- l. No evidence has been provided by the DI on the argument that China has surplus capacities. The DI has not considered the attractiveness of the market. The method of calculating surplus is also flawed. Surplus is calculated by deducting consumption of product in all markets and not just domestic market. The allegation is also immaterial since the source of information has not been disclosed, irrelevant in an original investigation, the understanding of "surplus capacity" is flawed, and there is no merit in the data. The DI must prove likelihood of diversion of surplus capacities to India. As held in *Indian Spinners Association v. Designated Authority*, mere surplus capacity cannot be seen as a foreseen and imminent threat of injury to the DI. Exports from China or excess capacity or increase in capacity do not necessarily mean dumping. Nothing concrete has been placed on record by the DI.
- m. The DI has not provided source for information on fluorspar prices. The rate of increase claimed by the DI is incorrect. Since two by-products are produced on the production of hydrogen fluoride from fluorspar, the changes in fluorspar prices do not directly affect prices of subject goods. The position of prices of fluorspar and subject goods is same as that of the DI. The DI itself has not stated that it uses fluorspar as its raw material. The prices of subject goods are affected by more important raw materials, market competition, supply chain and other matters.
- n. The imposition of ADD by the US is not relevant for the present investigation. The DI was itself investigated for circumvention. Hence, DI has no locus to rely on the argument. The imposition of ADD in the US did not lead to a spike in imports in India or impact on the DI. The imports are to meet demand-supply gap in India.

- o. Petitioner has not provided any evidence to support their claim that absence of third country imports is due to inability to match Chinese prices. The PUC is a new product that emerged in the international market which producers in China have prioritized unlike third country producers. Importers in India also prefer Chinese import due to reliability of supply. The domestic industry does not supply to refillers in India.
- p. The DI has claimed several expenses (advertising, other admin overheads, other selling and distribution overheads, commission on sales, discount/ rebate on sales, freight outward, and export related expenses) which should not be considered as per Annexure III of the AD Rules. NIP should be considered at ex-factory level.

H.3. Examination by the Authority

47. The submissions made by the domestic industry with regard to the injury and causal link related issues have been examined. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.
48. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of all the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis so made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
49. As regards the submission that alleged injury to the domestic industry is due to other reasons and there is no injury as per statements in annual reports of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory.
50. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand / apparent consumption

51. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	3429	7494	10235
Import from Subject Country- China	MT	634	1,974	3,810	5,503
Trend	Index	100	311	601	868
Imports from Other Countries	MT	-	-	-	-
Indian Demand/consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	393	782	1113

52. It is noted that the import of the subject goods from the subject country and the demand for the subject good have increased throughout the injury period. The Authority notes that the product is consumed in residential air conditioning and the domestic industry has stated that a surge is projected in the domestic AC production and India is likely to witness a robust growth in HFCs in the next decade due to robust growth in Air Conditioner (AC) market, coupled with substitution of HCFC 22 with HFC 32 & HFC 410A. Further, as against the present demand for the product established in the POI, the capacity with the domestic industry at the end of the POI was *** MT. The domestic industry has now announced further capacity expansion in respect of various flourochemicals, including the subject goods, and it has now been decided to expand capacities further.

b. Import Volumes from the subject country

53. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Factual position is as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Subject Country- China	MT	634	1,974	3,810	5,503
Trend	Index	100	311	601	868
Subject Imports in relation to					
Total Imports	%	100	100	100	100
Trend	Index	100	100	100	100
Production of PUC	MT	***	***	***	***
Production	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	69	110	142
Consumption	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	79	77	78

54. It is noted that:

- The volume of imports from the subject country has increased consistently over the injury period and the POI. The increase is consistent and significant.
- The subject imports constitute 100% of the total imports of the subject goods into India.
- The subject imports declined in 2017-18 in relation to Indian production, but increased thereafter in 2018-19 and the POI.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and selling price of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

Evolution of import prices over the injury period

Month	Rate (Rs/MT)
2016-17	1,70,236
2017-18	2,00,019
2018-19	2,34,355

Apr'19	1,79,410
May'19	1,71,542
June'19	1,70,841
Jul'19	1,68,412
Aug'19	1,67,745
Sep'19	1,69,991
Oct'19	1,76,855
Nov'19	1,45,214
Dec'19	1,46,086
Jan'20	1,35,687
Feb'20	1,37,294
Mar'20	1,38,952

a. Price undercutting

56. For the purpose of price undercutting analysis, net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from China. The Authority has calculated separate price undercutting for packed and unpacked forms in view of submissions by the interested parties and significant difference in the costs of packed and unpacked product.

Price Undercutting - POI	Unit	Total	Unpacked	Packed
Net Selling Price	₹/MT	***	***	***
Landed price (Subject Country China)	₹/MT	1,66,629	1,66,431	2,36,244
Price undercutting	₹/MT	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***
	Range	40-50	40-50	80-90

57. It is noted that the Chinese imports are undercutting the prices of the domestic industry in both packed and unpacked forms.

b. Price suppression and depression

58. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period have been examined. The Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales – Domestic	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>81</i>
Selling price - Domestic	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>66</i>	<i>60</i>
Landed Price	₹/MT	1,83,387	2,15,471	2,53,690	1,66,629
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>117</i>	<i>138</i>	<i>91</i>

59. It is noted that:

- Whereas the cost of production of the domestic industry has declined over the injury period, the selling price of the domestic industry has declined more than decline in cost of the domestic industry. The imports are depressing the prices of the domestic industry.
- During the period of investigation, the landed price of imports is below the cost of the domestic industry. Resultantly, whereas the cost has increased, the selling price of the domestic industry has declined during the period of investigation.

60. It is noted that the subject imports are depressing the prices of the domestic industry in the market.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

61. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

62. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, capacity, capacity utilization and sale

63. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>154</i>
Production of PUC	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>454</i>	<i>545</i>	<i>611</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>454</i>	<i>545</i>	<i>396</i>
Production including trial production at new plant	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>454</i>	<i>545</i>	<i>662</i>

64. It is noted that:

- The domestic industry was earlier undertaking manufacturing of HFC component in Bhiwadi Plant. The company commenced production of this product in 2016-17, which is the base year of the injury period in the present investigations. The plant has a capacity of *** MT.
- The domestic industry has expanded capacity and submitted that the same was in view of present and potential demand for the product in the country. However, the capacity expansion has been undertaken at Dahej. Further, whereas the Bhiwadi plant was of *** MT capacity, the Dahej plant has been set up with a capacity of *** MT and has commenced commercial production since November, 2019.
- With the commencement of production at Dahej in November, 2019, the domestic industry has submitted that it discontinued production at Bhiwadi. Therefore, the proportionate production for POI has been taken as *** MT.
- Since the company commenced commercial production at Bhiwadi plant in March, 2016, production was quite low in 2016-17 and increased thereafter. Resultantly, the capacity

utilization of the plant was also low in 2016-17 and increased thereafter till 2018-19. The capacity utilization, however, declined once again in the period of investigation.

- e. While production has increased consistently over the injury period, the capacity utilisation declined in the POI.
- f. The domestic industry had very low (practically negligible) volume of sales in 2016-17 and the production was largely consumed captively or was exported or was lying in stocks. Sales volumes, however, increased significantly thereafter till period of investigation.
- g. The domestic industry captively consumed part of the production.

ii. Market share in Demand

65. Market share of the domestic industry is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	894	982	941
China PR	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	79	77	78
Total	%	100	100	100	100

66. It is noted that the market share of the domestic industry increased till 2018-19 and declined thereafter during the POI. The market share of the subject country declined throughout the injury period and increased slightly in the POI. However, the market share of the subject country has remained significantly high throughout the injury period and POI.

iii. Inventories

67. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Opening Stock	MT	-	***	***	***
Trend	Index	-	100	76	127
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	76	100	256
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	176	176	383

68. It is noted that the inventories with the domestic industry have increased throughout the injury period. The domestic industry is holding 35 days inventories in stock, which is quite high considering the significant demand for the product.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

69. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below. Further, in view of the arguments of the interested parties that profits have declined due to increase in interest and depreciation costs, the profitability has also been examined by considering profit before interest and depreciation.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	61	46	-14
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Index	100	2131	3501	(***)

Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>340</i>	<i>365</i>	<i>128</i>
Profit before return & depreciation	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>345</i>	<i>382</i>	<i>158</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>269</i>	<i>242</i>	<i>-52</i>

70. It is noted that –

- Profitability has declined over the injury period. The domestic industry has suffered financial losses in the POI.
- Since the domestic industry had produced very low volumes in 2016-17 (after starting the plant), and sales increased over the injury period, profit before tax increased till 2018-19. Profit before tax however declined in the POI and the domestic industry suffered financial losses.
- Cash profit has improved slightly as compared to base year. Whereas profit per unit declined steeply over the injury period, gross profit earned on domestic sales increased till 2018-19.
- The Return on investment has increased in 2017-18 but declined as compared to the base year. Further, ROI was negative in the POI. It is seen that the performance of the domestic industry declined in respect of profit after interest.
- The Authority examined the reasons for so significant decline in profits, cash profits and ROI. It is noted that while some marginal decline could be attributed to increase in interest and depreciation costs, the decline in profits, cash profits and ROI is primarily due to decline in the selling prices.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>66</i>	<i>60</i>
Cost of production	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>81</i>
Profit/loss	₹/MT	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>61</i>	<i>46</i>	<i>(14)</i>
Depreciation	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>44</i>	<i>21</i>	<i>39</i>
Interest	₹/MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>59</i>	<i>71</i>	<i>86</i>

v. Employment, wages and productivity

71. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>684</i>	<i>1444</i>	<i>3117</i>
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>175</i>	<i>400</i>	<i>1238</i>

Wages Per Unit	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	151	265	510
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	161	95	94
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	454	545	611

72. It is noted that the wages, productivity and number of employees of the domestic industry have increased over the injury period. It is, however, noted that these were first a result of commencing new production at Bhiwadi in 2016 and then new production at Dahej in 2019. Further, the domestic industry has given the information only in so far as it relates to the PUC plant. There are captive inputs involved. The domestic industry has, however, not included that employment. In any case, the domestic industry has not claimed injury on this account. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

73. It is noted that the growth of the domestic industry was positive in respect of volume parameters and negative in respect of price parameters. Further, growth of the domestic industry in respect of volume parameters was below the optimal levels considered by the Authority.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production	Y/Y%	-	354	20	12
Domestic Sales	Y/Y%	-	3413	118	37
Cost of Sales	Y/Y%	-	2017	160	55
Selling Price	Y/Y%	-	-40	9	-9
Profit/Loss	Y/Y%	-	2031	64	-143
ROCE	Y/Y%	-	169	-10	-122

vii. Magnitude of Dumping Margin

74. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period. The domestic industry has submitted that the US Authorities have determined a dumping margin to the extent of 221% in respect of the product under consideration despite higher export price from China to USA as compared to India.

viii. Ability to raise capital investment

75. The domestic industry has not claimed injury on this account. It is seen that the domestic industry is a multi-product company. Investment decisions may not be based solely on the performance of a particular product during the injury period and may be governed by long term prospects of the product.

viii. Factors affecting domestic prices

76. It is seen that the domestic industry is the sole domestic supplier of the product. Further, product has been imported only from China, even though there is significant production in US and Japan (as stated by the domestic industry). Further, whereas the landed price of imports increased till 2018-19, the same has declined significantly in the POI. Further, the selling price of the domestic industry has also declined significantly over the period and in the POI. It is thus seen that import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is also seen that the landed value of the subject goods is below even the cost of production of the domestic industry in POI. The domestic industry submitted that it was not able to retain even the current prices in view of lower price of imports and resultant increasing imports. The price depression or suppression suffered by the

domestic industry is due to lower price of imports. Therefore, it is concluded that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject country.

ix. Magnitude of price underselling/injury margin

77. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined after detailed scrutiny of the information/ data relating to the cost of production provided by the domestic industry, duly certified by practicing accountant. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. Separate NIP has been determined for loose and packed form of the product. The NIP so determined has been considered for calculating injury margin.
78. Landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price adopted for the purpose of dumping margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/ exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
79. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters from China PR has been calculated by the Authority and the same is provided in the table below. Since the exporters have exported the product in unpacked form, the NIP of the domestic industry has been considered accordingly.

Sl. No.	Producer	Non-Injurious Price (US\$/MT)	Landed Price (US\$/MT)	Injury Margin (US\$/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
2.	Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. exported through Zhejiang Quhua Fluor-Chemistry Co., Ltd.	***	***	***	***	80-90
3.	Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. and Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd; exported through Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd.	***	***	***	***	70-80
4.	M/s Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	***	***	***	***	60-70
5.	All Others	***	***	***	***	90-100

H.3.4 Conclusion on Injury

80. It is noted that:

- The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject country has increased in absolute terms and in relative terms.
- The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive.
- The imports from the subject country are depressing the prices of the domestic industry.

- iv. The capacity utilization has declined significantly and inventories have increased for the domestic industry in the period of investigation.
- v. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profitability, profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry is suffering losses, cash losses and negative return on investments.

In view of the foregoing, it is concluded that the domestic industry has suffered material injury.

I. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

81. The Authority has examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry and notes as under:

a) Volume and value of imports not sold at dumped prices

82. Imports from China PR constitute 100% of the total imports of the subject good into India. There are no other countries which have exported the subject good to India during the POI.

b) Contraction in demand

83. The demand of the subject good has consistently increased during the injury period and the POI. In fact, considering the present and potential demand for the product in the country, the company has announced further expansion of the production capacities. The Authority notes that the domestic industry is fully capable of meeting the demand for the product in the country. However, the domestic industry is faced with unfair competition from imports at dumped prices.

c) Changes in Pattern of consumption

84. There have been no material adverse changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Rather, the pattern of consumption is improving in favour of the product, as is evident from the rising consumption in the country. The injury to the domestic industry found in the present investigation could not have been due to adverse changes in the pattern of consumption.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

85. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry. The PUC is produced only by one company in India and was exported only by one country.

e) Developments in technology

86. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. Further, the domestic industry has set up first plant in 2016 and second plant in August, 2019.

f) Export performance of the domestic industry

87. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

g) Performance of other products

88. The domestic industry has provided the injury data of PUC and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

Conclusion on Causal Link

89. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury in the POI due to other factors. Further, the following factors show that the injury to the domestic industry is due to subject dumped imports:

- a. The import price of the PUC increased between 2016-17 to 2018-19. The import price, however, declined steeply in the POI and was below even the levels prevalent in the base year. As a result of steep decline in the import price, selling price of the domestic industry increased in 2018-19 and then declined in the POI. As far as selling price of the domestic industry in 2016-17 is concerned, the Authority notes that the volume of sales was quite low and constituted primarily initial pricing offered by the domestic industry. There was 34% decline in the landed price of imports in the POI as compared to the preceding year. Resultantly, the domestic industry prices declined. However, the domestic industry reduced prices only by 9% and the same were already below cost of sales.
 - b. Despite price reduction by the domestic industry, the imports are undercutting the prices of the domestic industry. The landed price of imports is not only below the selling price of the domestic industry but also the cost of production in the POI.
 - c. The dumped imports are causing a significant suppressing and depressing effect on the prices of the product in the market.
 - d. The adverse impact of the imports on the selling price of the domestic industry has led to a significant decline in profitability. Resultantly, this has caused a significant deterioration in profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry is suffering financial losses, cash losses, and negative returns in the POI.
 - e. The growth of the domestic industry has become negative in respect of several economic parameters.
90. The Authority, thus, concludes that there exists a causal link between the dumping of the subject goods and injury to the domestic industry.

J. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

J.1 Submissions by the domestic industry

91. The submissions made by the domestic industry is as follows:
- a. The questionnaire responses filed by Mihama India Pvt. Ltd., Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and MPCL Industries Ltd. should be disregarded as they failed to provide any non-confidential version.
 - b. Normative performance of the domestic industry should be considered which shows injury to the domestic industry instead of considering actual capacity utilization.
 - c. As regards constructed normal value, wherever captive inputs are involved, reasonable profits are to be added to the captive inputs. The international raw material price may also be adopted.
 - d. The dumping margin is positive and substantial throughout the injury period and in the period of investigation.
 - e. No users or OEM or user associations have filed any verifiable information showing that there will be no significant or adverse impact on them.
 - f. Imposition of duties will arrest decline in the performance of the industry, redress the injury suffered and enable domestic producer to remain viable and competitive, and therefore in the interest of the consumers and the public at large.
 - g. If the current situation continues, the industry will face further injury and eventually be wiped out, giving the Chinese producers increased leverage, and the consumers will be left at their mercy. The consumers will have to maintain higher degree of inventory if they have to depend on imported material, while, in case of procurement from the domestic industry, inventory holding can be kept at much lower levels.
 - h. China's obligations to fulfil its commitments to the Kigali Amendment to the Montreal Protocol even before India's timelines only provides more incentive for China to dump the product under consideration so as to build a higher baseline before the phasing down begins.
 - i. The domestic industry has increased capacities to cater to the existing demand and has also planned to install more capacities to meet the rising demand.

- j. Anti-dumping duty will provide a level playing field not only to the domestic industry but also encourage imports from USA and Japan, leading to healthy competition.
- k. The imposition of duties is also consistent with the policy of the Government of India as the Central Government has been promoting the domestic manufacturing of air conditioners in the country through various policy measures.
- l. The increase in investments by the domestic industry will only lead to more employment, thereby benefitting the Indian economy as a whole. Further, it is of strategic importance for the country to have viable and environment friendly substitutes before the phase down of HFCs starts in the year 2032, which will only be possible if the industry is protected from dumping.
- m. It is in the country's interest as a whole to balance development within the country while also achieving its sustainable development goals. Failure to protect the domestic HFC industry will leave a weak link in the AC manufacturing supply chain and likely to be exploited by the Chinese manufacturers.
- n. Indigenous manufacturing helps ensure price stability of the product in the market, seamless supply, dependability on a reliable partner, import substitution, reduced foreign trade risk, growth of downstream industries.
- o. Due to the widening trade deficit and dwindling forex reserves, it is important to rely more on the domestic production capacities and reduce import dependence.
- p. The domestic industry is backward integrated and have made significant investments in the product under consideration. Therefore, there is a significant value addition done in the captive inputs.
- q. Since normal value is based on the data of the domestic industry, the same should be disclosed.
- r. The Authority should disclose the non-confidential version of the communication sent to participating exporters and replies if any, post filing of questionnaire responses, and verification reports.

J.2 Submissions by the other interested parties

92. The submissions of the other interested parties are as follows:

- a. Disregarding the details of the Chinese companies when determining normal value will nullify the provisions of the Article 15 (a) (ii) of China's Accession Protocol. The normal value for the respondent company should be determined on the basis of costs submitted by them which reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. No details regarding the proposed determination of normal value for Chinese producers has been disclosed or provided.
- b. The statements made by the domestic industry regarding injury have been accepted on their face value without objective examination of injury. Submissions on how the domestic industry has not suffered any injury due to the alleged imports have not been included or analysed in the disclosure statement.
- c. The figures of interest and depreciation of costs are given as per MT as compared to the petition to camouflage the information for these factors.
- d. Absence of examination or analysis on the submissions on non-attribution analysis in the disclosure statement, leads to the conclusion that injury is not due to the alleged imports but due to the impact of the other factors. There is no causal link between the alleged imports and the injury to the domestic industry.
- e. The dumping margin and injury margin should be determined based on quarterly analysis of prices, due to significant fluctuation in prices in different quarters of the period of investigation. Quarterly analysis for determination of dumping and injury margin was conducted in the *Sunset Review of anti-dumping duty on Viscose Staple Fibre from China PR*. The Respondents exported substantial quantities in the last two quarters when there was substantial decline in prices.
- f. The imports in relation to consumption has declined as such, the rate of increase in imports from China PR is in fact much lower than the rate of increase in demand. The Authority has not noted

the improving trend in the injury parameters including production, sales volume, capacity, and capacity utilisation.

- g. Decline in market share during the POI is inconsequential and observation made on the same is not an objective assessment of the economic parameters.
- h. The closure of Bhiwadi plant during the POI was not informed to the interested parties thereby limiting opportunity to comment on the change and impact on injury. The commencement of new plant and the discontinuation of the old plant has resulted in higher costs in the POI and cannot be attributed to alleged imports.
- i. The Authority should clarify if actual figures are taken for determining the economic parameters such as production for the POI.
- j. The impact of increased cost of sales in the period of investigation for NIP should be disregarded. The NIP has to be disclosed in range for each PCN as per Trade Notice No. 10/2018.
- k. The decline in profitability to the domestic industry is due to capacity expansion and due to resultant increase in finance cost and interest cost and the Authority has declined to recommend imposition in this regard in previous cases. The domestic industry will become profitable again once the production at Dahej normalises. The total increase in depreciation and total increase in interest cost has to be specifically noted.
- l. Veracity of information on the significant increase in wages per unit has to be ensured by the Authority.
- m. The decreased import price in the POI is because of consistent reduction of the Respondents cost of sales during the injury investigation period. There is no increased dumping in the period of investigation by the respondents.
- n. The significant difference in the information relating to profitability parameters provided in the petition and disclosed by the Authority in the disclosure statement requires clarification as the previous injury submissions are made based on the petition.
- o. Even though the imports of subject goods have increased, the rate is much lower than the growth in sales of the domestic industry and hence there is no volume injury. The decline in productivity indicate that injury is on account of inefficient work force management.
- p. Rejection of complete responses filed by the Sinochem Group is in violation of f Para 5 of the Annex II of Anti-Dumping Agreement. Export price of Qingsong, who is the exporter of the product under consideration has to be determined as sales price to Honeywell, who is the first independent buyer regardless of where the buyer is situated.
- q. Honeywell is an unrelated buyer and by imposing an overburden on their lack of assistance to the investigation on Qingsong and rejecting their response on this ground is not only violative of the principles of natural justice but arbitrary and violative of precedence and international practices. Sinochem Group has met all conditions required by the law when reporting the sales transactions.
- r. Qingsong is the exporter of product under consideration and issues commercial invoices to Honeywell and is also responsible for export declaration to China customs.
- s. Reliance is placed on the export price treatment by different jurisdictions such as EU, Canada and Australia, where export price has been determined by the sale price to the first independent buyer, which clearly shows that the export data of co-operating exporter cannot be rejected based on value chain.
- t. Imposing anti-dumping duties will have an adverse impact on the interests of the downstream industry and end users in India.
- u. The constructed normal value and non-injurious price determined by the Authority is highly excessive. The determination of export price and dumping margin has to be made as per the actual data provided by the respondent.
- v. A bulk-to-bulk comparison has to be made to determine the dumping and injury margin with separate analysis for packed and unpacked forms of product under consideration.

- w. The imposition of duty will result in monopolistic market as the petitioner is the sole producer of the subject good and subsequently affect the public interest and hinder the development of the industry in India.
- x. The domestic industry has not demonstrated how prices of subject goods have adversely impacted consumers. The process of filling the product under consideration in the AC is not a one-time process and needs to be carried out a number of times. The imposition of the duty is not in the consumer interest or the environmental objectives of the Government of India as the retail market for the product under consideration is cost sensitive.
- y. The duty protection is sought by the petitioner to protect its recent capacity expansion and investments from legitimate competition from Chinese imports. There is growing demand for the subject goods which cannot be met by the domestic industry alone.
- z. The increase in volume of subject imports should be seen in light of the demand supply gap for the product under consideration. The volume of imports in relation to demand declined as the domestic market share increased, indicating that subject imports are not a threat to the petitioner's growth.
- aa. The domestic industry has captively consumed part of its production which leaves the users and importers in the country to rely on imports from China and shows unreliability of petitioner.
- bb. No reason has been given for the discrepancy in the difference between high profitability parameters in the petition and the low profitability considered by the Authority. The data for aggregate profit/loss has not been disclosed for the period of investigation.
- cc. The petitioner's profitability has significantly improved over the injury period contrary to what has been observed by the Authority. The decline in financial performance during period of investigation is due to the decline of operational parameters.
- dd. Contrary to the claim of the petitioner, the performance of the economic parameters such as wages, employment and productivity is relevant to the determination of injury to the domestic industry.
- ee. The petitioner's refusal to supply product under consideration to refillers such as the respondent is commercially restrictive and an unfair trade practice.
- ff. The Authority is requested to limit the period of duty, if imposed, to a minimum period keeping in view the national strategy for phase-down of HFC to allow appropriate control of the production and consumption of HFC to ensure compliance with the Kigali Amendment by mid-2024.
- gg. Mihama imports product under consideration from its parent Company in Japan, which causes an already expensive product to be overpriced for sale in the Indian Market.
- hh. Since Mihama does not have a license for manufacturing and repackaging, utilization of contractors and sub-contractors for the same will increase overall cost of product under consideration.
- ii. The parent company of Mihama in Japan has established the subsidiary in India since the GOI would favour Japanese entities under various FTAs and has invested heavily with a view to establish and expand operations in India. Imposition of ADD will hinder further investments by the company.
- jj. The petitioner has grown manifold in the absence of injury as is evident from their operating cash flow statement. The client base of the petitioner outshines those of foreign exporters and importers. Levy of ADD will increase the market share of the petitioner from 50% to 90% resulting in price regulation and monopoly.

J.3 Examination by the Authority

93. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:

- a. As regards the argument of non-market economy status of China PR, material injury, causal link, injury due to increase in depreciation cost, anti-dumping duty will create monopoly for domestic industry, rejection of response by Mihama India Pvt. Ltd., Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and MPCL Industries Ltd and public interest, the same is addressed by the Authority in the relevant paragraphs of these findings.
- b. As regards objective examination of data, camouflage of figure of interest and depreciation costs and the differences in the data provided in the petition and in the disclosure statement, the Authority notes that the Authority has considered verified data of the domestic industry, for injury analysis.
- c. As regards quarterly examination, it is noted that the mere decline in the selling price does not mean a need for quarterly determination. The interested parties have established that the normal value has also materially changed with time period.
- d. As regards closure of Bhiwadi plant and commencement of Dahej plant has led to increase in cost, it is noted that the cost and NIP of Dahej plant is lower than Bhiwadi plant. Further, these are merely two plants of the domestic industry, and not two different legal entities.
- e. As regards actual figures considered for injury analysis, it is clarified that the Authority has considered actual verified figures of the domestic industry for injury analysis
- f. As regards the inability of the domestic industry to meet the demand-supply gap in the country, the Authority based on the information on records, notes that the domestic industry has increased capacity from *** MT during 2016-17, *** MT as on March, 2020 and *** MT (as on Jan 2021) as against the demand of *** MT. Further the capacity utilization of the domestic industry is low in the period of investigation and has declined as compared to the preceding year. The domestic industry had the potential to cater the much higher degree of demand in India. However due to dumping of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity and had a much smaller share in domestic market as compared to Chinese imports. The domestic industry has further announced increase in capacity by *** MT of fluorocarbon refrigerants and certain key raw materials by July 2023 with an investment of around *** crore; in order to cater the present and potential demand of the product under consideration in India. In any case, a possible demand-supply gap does not justify dumping of the product under consideration, particularly when such dumping is causing injury to the domestic industry.
- g. As regards disclosure of PCN wise NIP, it is clarified that the Authority has not considered PCN in the present investigation.
- h. As regards rejection of responses filed by the Sinochem Group, it is noted that since, the information in respect of exports made by Honeywell Trading (Shanghai) Co., Ltd, the Authority has not considered the responses filed by the producer and exporter for determination of the export price. The Authority has adopted its consistent practice while rejecting the response of the exporter where the details of major share of exports made by the responding producer is not on record.
- i. As regards the argument of addition reasonable profits to captive inputs while calculating normal value, it is clarified that the Authority has not added profits in captive inputs as per its practice. All captive inputs have been transferred at their cost of production and profit has been added as a percentage of total cost of production.
- j. As regards submissions of Mihama India Pvt. Ltd., it is clarified that the subject goods in concerned are imports of Hydrofluorocarbon (HFC) Component R-32, originating in or exported from China PR only.

K. INDIAN INDUSTRY INTERESTS AND OTHER ISSUES

94. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The

purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

95. The Authority considered whether imposition of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the imposition of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
96. The Authority issued gazette notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to present investigations, including possible effect of ADD on their operations. The Authority sought information on, inter-alia interchange ability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the domestic industry to switch sources, effect of ADD on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of ADD.
97. Four importers, namely, M/s Refex Industries Ltd., M/s MPCL Industries Ltd., M/s Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and M/s Mihama India Pvt. Ltd. have responded to the present investigation. Only M/s. Refex Industries Ltd. has filed the questionnaire response in the manner prescribed by the Authority. M/s MPCL Industries Ltd., M/s Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and M/s Mihama India Pvt. Ltd., did not circulate non-confidential version of their responses/submissions to the other interested parties. The Authority has considered the arguments of all interested parties in the present finding and rejected response/submissions filed by M/s MPCL Industries Ltd., M/s Stallion India Fluorochemicals Pvt. Ltd. and M/s Mihama India Pvt. Ltd. None of the users, OEMs or user associations have opposed to the present investigation. Nor these parties have claimed that there shall be adverse effect of proposed ADD on public at large, or even their operations. As already noted in these findings, none of these importers have provided any verifiable information to demonstrate the effect of anti-dumping duty on the consumers. Further, in this regard, the Authority re-iterates that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
98. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that none of the interested parties have provided relevant information. It is, thus, noted that the interested parties have not established impact of ADD on the user industry with verifiable information. Further the domestic industry has quantified the impact of the recommended anti-dumping duty on the consumer industry and submitted that the impact is meagre.
99. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence in their post hearing written submissions that the PUC is produced globally in China having capacity of 2,84,000 MT, US having capacity of 25,000 MT, India having capacity of *** MT; South Korea having capacity of 9500 MT and Japan having capacity of 6000 MT. The product is under free category and, therefore, can be freely imported from various countries. Imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from China in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would neither affect the availability of the product to the consumers nor create monopoly.
100. The United States of America has also investigated the imports of the product under consideration into USA from China PR. The United States imposed a significant quantum of duties on the said imports, on finding that the imports are causing material injury to their domestic industry. The quantum of duties levied by the US Authorities ranges from 161%- 221% which indicates the level of dumping that China is resorting to, in other countries.
101. The Authority notes that the product is consumed mainly in residential air conditioning and the domestic industry has stated that a surge is projected in the domestic AC production and India is likely to witness a robust growth in HFCs in the next decade due to robust growth in Air Conditioner (AC)

market, coupled with substitution of HCFC 22 with HFC 32 & HFC 410A. The domestic industry has increased capacity from ***MT during 2016-17, *** MT as on March, 2020 and *** MT (as on Jan 2021). The domestic industry has further announced an investment of around Rs *** crore to increase the existing capacity from ***MT to ***MT of the product under consideration, by July 2023; in order to cater the present and potential demand of the product under consideration in India.

102. Further the capacity utilization of the domestic industry is low in the period of investigation and declined as compared to preceding year. The domestic industry had the potential to cater the much higher degree of demand in India. However due to dumping of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity and had a much smaller share in domestic market as compared to Chinese imports. The Authority also notes that even when there are significant capacities in US and Japan, there are no imports from these countries. The domestic industry contended that dumping by Chinese producers has prevented these countries from selling in the Indian market.
103. It is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry has submitted that the cost of product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. For example, assuming that an air conditioner of a capacity of 1 Ton costs in the range of Rs. 20,000 to 40,000. The amount of HFC Component R-32 used in the air conditioner would be less than 1 kg. Assuming that 1 kg of HFC Component R-32 costs around Rs. 200, the cost of the product under consideration on the end-consumer of the final product is very meagre. The interested parties contended that use of the product is not one time and there are multiple refill. The Authority however notes that if the entire cost of the product in an AC is just Rs. 200, even costs on account of refill are not significant.
104. It is, thus, noted that while the interested parties have not established possible adverse impact of proposed ADD on the user industry with verifiable information. Thus, even if it is considered that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods, the impact of the antidumping duty on the eventual product would be grossly insignificant. Further, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. The objective of imposition of anti-dumping measure is to remove the unfair advantages gained by dumping practices; to prevent the injury to the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
105. The Authority further notes that the recommendation for imposition of duty is made only when the requisite legal requirements are met. The interested parties contended that the domestic industry has been using trade defence quite often. It is, however, noted that the domestic industry has reported that it is engaged in production of 71 products and is at present protected by ADD in 4 products. The ADD earlier in force on imports of nylon tyre cord fabric and methylene chloride from China is no longer in force.
106. From the information on record, it is also noted that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration, and the Authority is of the view that the imposition of anti-dumping duty will be in public interest.

L. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

107. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
 - a. The Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - b. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country.
 - c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of investigation and the application contained sufficient evidence to justify initiation of the investigation.

- d. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined, and the margins are significant.
- e. The domestic industry has suffered material injury. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from China increased significantly in absolute terms and remained significant despite significant capacity addition by the domestic industry and increase in its production. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. The imports are depressing the prices of the domestic industry. The capacity utilization declined significantly after increasing upto 2018-19, inventories have increased industry in the period of investigation. The performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of per unit profitability, profits, cash profits and return on capital employed. The domestic industry is faced with unutilised capacities despite significant demand in the Country, and demand-supply gap in the POI.
- f. The material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports.
- g. Despite providing sufficient opportunity to interested parties to quantify the impact of ADD and elaborate on how imposition of ADD will adversely impact them, none of the consumers have demonstrated possible adverse effect. Information on record shows that non imposition of anti-dumping duty will adversely and materially impact the indigenous production, while imposition of duty will not materially impact the consumer or downstream industry or public at large. On the basis of information provided by interested parties and investigation conducted, the Authority is of the considered view that the imposition of anti-dumping duty will not be against public interest.
108. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of proposed measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, and having quantified the impact of non imposition and imposition of ADD, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
109. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of antidumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject country, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below' The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	290339	Hydrofluorocarbon Component R-32	China PR	Any country including China PR	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	1,171.78	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd.	1,394.96	MT	US\$

3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. and Fujian Qingliu Dongying Chemical Ind. Co., Ltd;	1,344.60	MT	US\$
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.	1,255.05	MT	US\$
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other than S N 1 to 4	1,519.70	MT	US\$
6	-do-	-do-	Any other country other than China PR	China PR	Any	1,519.70	MT	US\$

M. FURTHER PROCEDURE

110. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the appropriate Forum.

ANANT SWARUP, Designated Authority